THE LOK SABHA REASSEMBLED AFTER LUNCH AT THREE MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK.

(Mr. Speaker *in the Chair*).

RE : BUSINESS OF THE HOUSE *–Contd.*

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : On a point of order, Sir. My point of order is this. First of all the House has to decide whether the No-confidence Motion is to be taken up first or the Adjournment Motion is to be taken up first. We were expecting that the Adjournment Motion will be taken up first. This is an important issue of exodus of refugees from Pakistan. The Government has all along taken a callous, heartless, even cruel attitude to the minorities. Every day 1600 refugees are entering into India. This is a subject which should have been given priority. 60,000 refugees are suffering and they are put in inhuman condition. This matter has been discussed in the Rajya Sabha for the whole day yesterday. Daily 1600 people are coming. When the Prime Minister visited Calcutta, she did not care to go to that area. I wrote to her several letters and I sent her telegrams but she had not cared to visit that place. So, it is necessary that the Adjournment Motion should be taken up first and the No-confidence Motion may be taken up tomorrow.

MR. SPEAKER : This has already been fixed.

SHRI SAMAR GUHA : As a protest I walk out. All this shows the inhuman, heartless, cruel, callous attitude of this Government towards the refugees and the minorities. You have not allowed this House to discuss this very important matter. In protest, I walk out.

(*Shri Samar Guha then left the House*)

श्री कंवर लाल गुप्ता (दिल्ली-सदर) : अध्यक्ष महोदय, यह कितनी देर चलेगा ?

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : You may ask the Minister to make a Statement at least on which we can discuss the entire issue.

अध्यक्ष महोदय : जो चीज तय हो चुकी है, उसे चलने दीजिए। यह तरीका है, जिस की मर्जी आती है वही बोलने लगता है।

SHRI S. M. BANERJEE : Let the Minister make a statement. More than 2 lakhs of people have come.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Why should opportunity be given to the other House to discuss this while we are not given an opportunity to do so ?

MR. SPEAKER : I have already sent the notice to the hon. Minister, and I shall let the hon. Member know.

SHRI S. M. BANERJEE : Let the hon. Minister make a statement today at six o' clock. We are prepared to wait. Let us have a discussion on that statement some time tomorrow.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, साउथ ईस्टर्न रेलवे और नार्थ ईस्टर्न फ्रांटियर रेलवे के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस पर बहुत हंगामा मचा हुआ है। रेलवे मंत्री इस पर बयान दे सकते हैं. आप उन से कहें कि वे इस पर बयान दें।

14.06 hrs.

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS *Contd.*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश कर रहा हूं। अविश्वास का प्रस्ताव हो या काम रोको प्रस्ताव हो या

[श्री मधु लिमये]

असहमति प्रकट करने का प्रस्ताव हो- ये सारे संसदीय तरीके हैं जनता के सवालों पर यहां बहस उठाने के। अगर आज हमारे मंत्री लोग अन्तरआत्मा की पुकार को सुनेंगे तो शायद वोट के समय वे हमारे प्रस्ताव के हक में वोट देंगे, लेकिन अगर कुर्सी के मोह से-इन लोगों को जो बड़ी बड़ी कोठियां मिलती हैं, एक एक मील लम्बी अमरीकन गाड़ियां मिलती हैं, अगर इन सारी चीजों के मोह से मुक्त हो जायेंगे, तो जरूर अन्तरआत्मा की आवाज सुन पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के दो हिस्से हैं—पहले प्रस्ताव में यह कहा गया है कि ऐसे जनतंत्र विरोधी हथकण्डे अपनाये जा रहे हैं, जिन से केरल में जो चुनाव होने वाला है, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में नहीं हो पायेगा। आप पूछ सकते हैं कि केरल के चुनाव का मसला हम लोग यहां पर क्यों उठा रहे हैं? क्या इलैक्शन कमीशन संविधान के अन्दर एक स्वतंत्र हैसियत नहीं रखता है और क्या उनके द्वारा जो तिथियां निश्चित की जाती हैं, उन के बारे में हम लोग दखल दे सकते हैं? तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब यह होगा कि इलैक्शन कमीशन को यह भली-भांति मालूम था कि लोक सभा में इस विषय पर बहस होने जा रही है, ऐसी स्थिति में उन को चाहिए था, उन का यह नैतिक फर्ज था कि बहस के दौरान क्या बातें आती हैं, कौन से दृष्टि कोण रखे जाते हैं, उन को सुनने के बाद उनका अध्ययन करने के बाद, उन को जो निर्णय करना था, वह उन्हें करना चाहिये था। लेकिन यह निर्णय, जो इतनी जल्दबाजी में किया गया है इस के पीछे मुझे कोई रहस्य मालूम पड़ता है। पार्लियामेंट के सामने जब यह मसला है और यह समूचे राष्ट्र की पंचायत है, तो उसको विचार करने का मौका देने के पहले ही इलैक्शन कमीशन जब इस तरह का निर्णय करता है तो इसका साफ मतलब है कि उन के ऊपर संविधान में जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका उन्होंने पालन नहीं किया है। कम से कम हमारी बातों को उन्हें पढ़ना चाहिये था, सुनना चाहिये था, समझने की कोशिश करनी चाहिये थी।

केरल के चुनावों की पृष्ठभूमि क्या है? चुनाव जल्द हो या कुछ विलम्ब किया जाय-इस में यह सवाल नहीं है। इस में दो सवाल जुड़े हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि चुनाव जल्द हों, लेकिन चुनाव का जो आधार होगा—मतदाता सूची-अगर मतदाता सूची में हैरा-फेरी की गई है, अगर जाली सूची बन गई है, तो उसके अधार पर जो चुनाव होगा, वह निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पायेगा, जनता की राय का सही मामलों में उस में प्रतिबिम्ब नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि मतदाताओं की जो सूची तैयार की गई है वह बिल्कुल जाली सूची है। उसके कुछ सबूत मैं पेश करना चाहता हूं। कुल मतदाताओं की संख्या 86 लाख के आसपास है। लेकिन अच्युत मेनन सरकार की निगरानी में नयी सूची बनाई गई है और हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि इलैक्शन कमीशन तो स्वतंत्र हैसियत रखता है लेकिन मतदाता सूची तैयार कराने या चुनाव कराने की जो सारी मशीनरी है वह राज्य सरकारों की मशीनरी होती है और इसलिए अच्युत मेनन सरकार की निगरानी में जो सूची बनी है वह कैसे जाली है इसके दो सबूत मैं पेश करना चाहता हूं। कुल 86 लाख मतदाता पहले थे लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस नयी सूची में से 17 लाख मतदाता छांट दिये गये हैं। आप लोग जानते हैं कि केरल में मौतें इतनी तेजी से नहीं होती हैं। आप सेन्सस रपट देख लेंगे तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान में मौत का अनुपात सबसे कम केरल में है। इस वक्त मैं इस पर आ रहा हूं कि 17

लाख लोगों को कैसे छांट दिया गया क्योंकि ये तकरीबन 20 परसेंट हो जाते हैं। क्या अच्युत मेनन की सरकार का यह कहना है या इलैक्शन कमीशन का यह कहना है कि केरल में लोग इतनी तेजी से मरते हैं कि तीन साल में 20 प्रतिशत प्रौढ़ मतदाता खत्म हो गए ?—(व्यवधान)—

अब आप दूसरा पहलू भी देख लीजिए। नयी सूची में 31 लाख नये मतदाता जोड़ दिये गये हैं जिसका मतलब है कि प्रौढ़ मतदाताओं में 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम सभी जानते हैं कि केरल के जो लोग हैं, चाहे ईसाई हों, हिन्दू हों या मुसलमान हों वे परिवार नियोजन में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, उनके बड़े परिवार होते हैं। मैं इस बात को मानता हूं लेकिन क्या हर साल प्रौढ़ मतदाताओं में 12 प्रतिशत की वृद्धि केरल में भी हो सकती है ? ढाई प्रतिशत के अनुपात से जनसंख्या बढ़ रही है तो केरल में तीन प्रतिशत तक मान लीजिए। इसलिए इससे साफ हो गया कि यह मतदाता सूची बिल्कुल जाली है और जबतक इस सूची में ठीक ढंग से परिवर्तन नहीं होता—यानी जिस तरीके से 17 लाख लोगों को छांट दिया गया है और नये 31 लाख लोगों को जोड़ दिया गया है, ये दोनों काम जाली हैं इसलिए मतदाता सूची में जबतक सुधार नहीं होता तबतक चुनाव करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मतदाता सूची ठीक ढंग से सुधारी जाती और उसके बाद चुनाव की तारीख तय की जाती तो बात समझ में आ सकती थी।

दूसरी बात यह है। जिस ढंग से केरल में अच्युत मेनन की सरकार को जीवित रखा गया है उस स्थिति के उधर भी आप गौर फरमायें। मार्च में विधान सभा की बैठक हुई थी और मेरा ख्याल है कि 9-10 अप्रैल तक विधान सभा की बैठक का कार्यक्रम बन चुका था, कई अध्यादेश, आर्डिनेन्सेज ये जिनको विरोधों के रूप में पास कराने का काम करना था तो क्या वजह थी कि जब 9-10 अप्रैल तक विधान सभा की बैठक का कार्यक्रम निश्चित था तो तकरीबन 15-16 दिन पहले ही विधान सभा की बैठक को अचानक स्थगित कर दिया गया ? अचानक इसलिए स्थगित किया गया कि अखबारों में खबरें आई थीं, मुझे याद है गौरी टामस का बयान आया था कि 73 लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हम इस सरकार को गिरायेंगे। हो सकता है कि उनके बयान में तथ्य हो। यह भी मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं कि शायद अगर शक्ति परीक्षा होती तो उनका जो यह बयान था वह सही नहीं निकलता लेकिन वह एक विवाद की बात है परन्तु जब विधान सभा की बैठक 9-10 अप्रैल तक चलने वाली थी तो क्या यह जनतांत्रिक परम्परा के अनुकूल है कि विधान सभा की बैठक को इस तरह से अचानक स्थगित कर दिया जाये ? मध्य प्रदेश के बारे में कई दफा हम इस पर बहस कर चुके हैं और मेरी राय में जनतन्त्र की जो स्वस्थ परम्परा है उसके यह बिल्कुल विपरीत है। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। इतना ही नहीं, अच्युत मेनन साहब गवर्नर से जाकर मिलते हैं, परामर्श करते हैं, किसी को पता नहीं और अचानक हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि विधान सभा को भंग कर दिया गया है। मैंने अपने प्रस्ताव में जो कहा है कि विधान सभा का विश्वास यह सरकार खो चुकी थी तो यह मैं दो मुद्दों के आधार पर साबित करना चाहता हूं। बैठक की निश्चित तिथि, अवधि 9-10 अप्रैल तक थी, उसको अचानक स्थगित किया गया। इतना ही नहीं, विधान सभा को भंग करने का जो काम है उसमें, केरल की सरकार में जो अन्य घटक पक्ष थे, अन्य दल थे उनसे भी सलाह मशिवरा नहीं किया गया, उनसे पूछा तक नहीं गया। अखबारों में जो उनके बयानात आये हैं उनसे साफ हो जाता है कि उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया। तो क्या आप मानते हैं कि

[श्री मधु लिमये]

गवर्नर ने अपनी जिम्मेदारी पर यह निर्णय किया ? हम कई लोग कई बार इस सदन में साबित कर चुके हैं कि आज सूबों के जितने गवर्नर हैं वे अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं, केन्द्र के इशारे पर चलते हैं। केन्द्र के इशारे पर हमेशा ये काम हुआ करते हैं। तो अच्युत मेनन की सरकार को जीवित रखना, विधान सभा को भंग करना और उसके बाद भी मेनन सरकार को भंग न करना, यह सारा काम केन्द्र की सलाह से और केन्द्र के कहने पर हुआ है। इसलिए मैं अच्युत मेनन की सरकार की इन्दिरा सरकार की एजेन्सी मानता हूँ। मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है लेकिन केन्द्रीय सरकार की एजेन्सी बनकर क्या वे केरल की जनता का कल्याण कर सकते हैं ? ···(व्यवधान)··· इसलिए मेरा आक्षेप है कि अच्युत मेनन की सरकार को एक सेकेण्ड के लिए भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं था। असेम्बली को भंग करने के पश्चात् कम से कम नैतिकता का तकाजा था कि वे तत्काल अपना इस्तीफा देते लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ? क्योंकि मतदाता सूची में हेरा-फेरी करने का काम करने के लिए उनको मौका मिले और चुनाव जीतने की दृष्टि से कुछ ऐसा दमन और आतंक का वातावरण बनाया जायें जिससे कि जो विरोधी दल हैं वे दब जायें और जाली मतसूची के जरिये तथा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने में आसानी हो। मैं केरल के सवाल पर आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी वहां पर हुआ है वह सभी दृष्टि से अनुचित हुआ है। मतदाताओं की जो सूची है उसमें सुधार किये बिना इस तरह चुनाव करने का कोई मतलब नहीं है और अच्युत मेनन सरकार को भी एक क्षण के लिए सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)···वासुदेवन नैयर साहब मुझे टोक रहे हैं लेकिन जब श्री गोविन्द मेनन साहब ने इसी तरह से वहां पर अपनी सरकार को जीवित रखा था तो ये हम लोगों का साथ देते थे कि यह अनैतिक काम है लेकिन आज वे टोक रहे हैं तो कोई बात नहीं। ···(व्यवधान)

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : They should have resigned and gone. The Assembly is dissolved. How can they hang on like the Babylonian hanging gardens ?

श्री मधु लिमये : अब इस प्रस्ताव का जो दूसरा आधार है उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। इस प्रस्ताव में मैंने कहा है कि सरकार की जो पुनर्गठन की गई उससे, एक अरसे से जो केन्द्रीकरण का संकट उत्पन्न हुआ था वह केन्द्रीकरण का संकट और गम्भीर हो गया है। सभी लोग जानते है कि प्रधान मन्त्री सरकार का नेतृत्व करती है लेकिन इसका कभी यह मतलब नहीं होना चाहिये कि सारे सरकारी महत्वपूर्ण अधिकार वे अपने हाथ में केन्द्रित करें। मन्त्रि-मण्डल की पुनर्रचना के बाद उनके हाथ में जो अधिकार आये हैं उनकी अगर हम सूची देख लेते हैं तो मैंने जो कहा है उसमें कितना तथ्य है, उसका पता आपको चल जायेगा ; उनके पिता जी के कार्य-काल में भी प्रधान मन्त्री ने अपने हाथ में ऐटमिक एनर्जी और कैबिनेट सेक्रेटेरियट विभाग रखे थे। शास्त्री जी के जमाने में भी ऐसा था। लेकिन अब क्या हो गया ? सत्ता का इतना ज्यादा केन्द्रीकरण हुआ है कि जिन तानाशाही देशों में, एकाधिकारशाही वाले देशों में सत्ता का बहुत ज्यादा केन्द्रीकरण हुआ है, ऐसा हम कहते हैं, उन देशों में भी किसी भी समय स्टैलिन ने, हिटलर ने या मुसोलिनी ने व्यक्तिगत रूप में इतनी सत्ता अपने हाथ में नहीं रखी थी। वहां पार्टी एकाधिकारशाही जरूर थी, गुट एकाधिकारशाही जरूर थी, मगर सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं। यहां लोकतन्त्री ढांचा है, संसद है, विधान सभा में चल रही है। फिर भी आज यहां सत्ता का केन्द्रीकरण एक व्यक्ति के हाथ में तेजी से हो रहा है।

केन्द्र के पांच जासूसी विभाग हैं। अब प्रधानमन्त्री ने पांचों विभाग अपने हाथ में ले लिये हैं, घुमा फिरा कर ले लिये हैं अपने हाथ में ; फौजी जासूसी विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सैंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन। इतना ही नहीं ; जब उन्होंने वित्त मन्त्रालय श्री चव्हाण को दिया तो पहले वह "नहीं-नहीं" कहते थे, कम से कम अखबारों में यह बात आई थी और उस से इन्कार नहीं हुआ था, लेकिन अन्त में उन को राजी किया गया कि वह वित्त मंत्रालय को ले लें। लेकिन क्या हुआ ? वित्त मंत्रालय से दो प्रमुख जासूसी विभागों को उन से छीन लिया गया। रेवेन्यू इन्टेलिजेंस और एन्फोर्समेंट डाइरेक्टोरेट। श्री चव्हाण पहले वित्त मंत्री है जिन के हाथ में यह दोनों विभाग नहीं है ; आप किसी को जंग के मैदान में भेजते हैं, लेकिन उस के जो हथियार हैं उन को आप उन से छीन लेते हैं और कहते हैं . कि लड़ाई लड़ो।

एक माननीय सदस्य : बहादुर हैं, लड़ाई वगैर हथियार के लड़ते हैं।

श्री मधु लिमये : बहादुर हैं या क्या हैं, इस का फैसला आप बाद में कीजियेगा। लेकिन उस का नतीजा यह हुआ है। वित्त मंत्रालय के दो जासूसी विभाग हैं। रेवेन्यू इन्टेलिजेंस और एन्फोर्समेंट डाइरेक्टोरेट। विदेशी मुद्रा का जितना उल्लंघन होता है उसका सम्बन्ध एनेफर्समेंट डाइरेक्टोरेट से होता है और इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आदि जो केन्द्र के कर हैं उनके बारे में रेवेन्यू इंटेलिजेंस काम करता है। श्री मोरार जी देसाई के जमाने में भी रेवेन्यू इंटेलिजेंस की पुनर्रचना की गई थी और श्रीवास्तव जी को लाया गया था, लेकिन आज यह दोनों जासूसी विभाग प्रधान मंत्री ने अपने हाथ में ले लिये। जब इतनी सत्ता आज वह अपने हाथ में रखना चाहती हैं तो मुझे ऐसा लगता है, कि यह लोकतन्त्र के स्वास्थ्य के लिये अच्छा नहीं है, मुल्क के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और इन्सान के नाते उनके स्वास्थ्य के लिये भी अच्छा नहीं है। इतनी सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में आयेगी तो उस का स्वास्थ्य अच्छा नही रहेगा। (**व्यवधान**) में नैतिक स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, शारीरिक स्वास्थ्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं।

इन पांच जासूसी विभागों के अलावा, कैबिनेट सेक्रेटेरियट के संबंध में जो नया गजट प्रकाशित हुआ है उस से पता चलता है कि बहुत से नये नये विभाग कैबिनेट सेक्रेटेरियट में लाये गये। मैं आप के सामने तीन बातें रखना चाहता हूं ; एलेक्ट्रानिक्स विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और ऐसा विभाग है जो डिफेंस मंत्रालय में आता था और शायद कुछ हिस्सा औद्योगिक विकास मंत्रालय में भी आता था। लेकिन यह एलेक्ट्रानिक्स विभाग कैबिनेट सेक्रेटेरियट में लाया गया। आज तक हम मानते थे कि सरकारी काय के जितने विभाग हैं वह एक मंत्री के सुपुर्द किए जाते है, लेकिन आज एक नया ही विभाग बन रहा है कैबिनेट सेक्रेटेरियट। यह नया राक्षस है और सब कुछ स्वाहा कर रहा है। कैबिनेट सेक्रेटेरियट के अन्दर एलेक्ट्रानिक्स विभाग चला गया। डिपार्टमेंट आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च भी उसी सेक्रेटेरिएट में है। अर्थात् सारी औद्योगिक और वैज्ञानिक शोध की मालिक प्रधान मन्त्री बन गई हैं।

दूसरा सब से बड़ा परिवर्तन प्रधान मन्त्री ने यह किया कि उन्होंने डिपार्टमेंट आफ पर्सोनेल अपने हाथ में ले लिया। यानी प्रधान मन्त्री के नाते जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और अफसर थे वह उनके प्रति वफादार तो थे ही, लेकिन इस से उन्हें सन्तोष नहीं हुआ। उन्होंने पार्सोनेल ऐडमिनिस्ट्रेशन भी ले लिया। वह यह सफाई दे सकती है कि किसी कमीशन ने यह सिफारिश की थी, लेकिन उस कमीशन को बाकी जितनी

(श्री मधु लिमये)

सिफारिशें थीं उनको वह मिट्टी में मिलाती हैं मगर जो सत्ता के केन्द्रीकरण वाली सिफारिशें हैं उनको वह अपने हाथ में एकत्रित करती जा रही हैं ।

एक माननीय सदस्य : कमिशन वाले तो यहां बैठे हैं ।

श्री मधु लिमये : कमिशन वाले जो बैठे है वह कुर्सी के मोह में रहेंगे या ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिशन की सिफारिशों के बारे में उत्साह दिखलायेंगे यह हम देखने वाले है। उन्होंने डिपार्टमेंट आफ पार्सोनेल अपने हाथ में लिया, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है । उन्होंने एक कमिटेड सिविल सर्विस की बात कही थी। कमिटमेंट, टु हूम ? सामाजिक आदर्श के प्रति या उन के व्यक्तित्व के प्रति ? कमिटमेंट टु दि प्राइम मिनिस्टर ?

इसके अलावा और भी विभाग आप देख लीजिए । यह जो उद्योग विभाग था उसको जिस तरह से खण्डित किया गया उसके पीछे बड़ी नीति का सवाल उत्पन्न होता है । उद्योग विभाग को खण्डित किया गया । और श्री दिनेश सिंह की प्रतिभा भी खण्डित हो गई । आज वह कहां है यह पता नहीं ।

एक माननीय सदस्य : रब्बात में ।

श्री मधु लिमये : रब्बात में तो विदेशियों ने चपत मारी,अब तो घर वाले ऐसा कर रहे हैं । हुआ क्या उद्योग मंत्रालय का ? उद्योग मंत्रालय से कम्पनी कानून विभाग अलग कर दिया गया । यह कम्पनी कानून विभाग भी एक विचित्र विभाग है । जब कृष्णमाचारी वित्त मंत्री थे तब वह इस बात पर अड़ते थे कि कम्पनी कानून विभाग मेरे हाथ में होना चाहिए और वह वित्त मंत्रालय के साथ जुड़ता था । बाद में जब श्री मोरार जी देसाई बने तो ओहदा तो बड़ा बन गया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन कम्पनी कानून विभाग उन से अलग कर दिया गया और श्री फखरुद्दीनअली अहमद के साथ जोड़ा गया । आज कम्पनी कानून विभाग अलग कर के एक राज्य मंत्र के हाथ में देने के पीछे क्या रहस्य है? एक राज्य मंत्री के हाथ में इतना महत्वपूर्ण विभाग ?

औद्योगिक विकास के बारे में क्या हुआ ? श्री दिनेशसिंह ने एक बयान दिया कि हो सकता है कि कम्पनी विभाग मेरे साथ न हो, मगर अखबार वालों से उन्होंने कहा कि लाइसेंसिंग तो मेरे हाथ में है । दूसरे दिन प्रधान मंत्री ने पत्र द्वारा उन को सूचित किया कि मैं ने तय किया है कि एक कमेटी बने लाइसेंसिंग के बारे में और उस की अध्यक्ष मैं बन जाऊंगी । इस तरह से लाइसेंसिंग विभाग भी अपने हाथ में ले लिया । अब श्री दिनेश सिंह के हाथ में रहा क्या ? एक मील लम्बी मोटर कार, एक कोठी और कुर्सी । सत्ता का जितना ज्यादा केन्द्रीकरण हो रहा है इस पर आप सोचिए । गृह मंत्रालय उन्होंने ले लिया और गृह मंत्रालय के कार्य का विभाजन कैसे हुआ ? जम्मू और काश्मीर उन के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज की नियुक्तियां उनके हाथ में, गवर्नर और लेफ्टेनेंट गवर्नर की नियुक्तियां उनके हाथ में ।

एक माननीय सदस्य : बहुत मजबूत हाथ हैं ।

श्री मधु लिमये : और मजबूत करो ।

एक माननीय सदस्य : आप भी आइयेगा उन के हाथ में ।

श्री मधु लिमये : हम को छोड़िये । आखिर कार इस सारी सत्ता के केन्द्रीकरण का मकसद क्या है ? इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स डिस्क्रीशनरी फंड भी होता है, उस का कोई हिसाब किताब नहीं रहता । देने की कोई जरूरत नहीं

और गृह मंत्रालय के यह सारे जो कार्य हैं वह भी आज उन्होंने अपने हाथ में ले लिया।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष इन्होंने वित्त मंत्रालय अपने हाथ में लिया और यह कहकर लिया कि यह श्री मोरारजी देसाई बहुत अड़ंगे डालते हैं, मैं कुछ करना चाहती हूं और इसलिए मैं इस विभाग को अपने हाथ में ले रही हूं। उसके बाद चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ; एक साल तक वित्त मंत्री के नाते बने रहने के बाद इन्होंने जिस अयोग्यता का परिचय दिया क्या उसके ऊपर यह सदन विचार नहीं करेगा? एक साल में वित्त मंत्री के नाते इन्होंने किया क्या, इन्होंने कहा क्या था? एक साल के बाद भी बैंकों के बारे में कोई योजना नहीं बनी है। इन्होंने जितने बयान दिये, उनके विपरीत काम हुआ। शुरू में बयान आए कि डिपाजिट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले वर्ष में डिपाजिट्स सिर्फ बारह प्रतिशत के आसपास बढ़े हैं लेकिन जो कर्जा दिया जाता है, जो क्रेडिट दिया जाता है वह सतरह प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। बैंक डिपाजिट्स को इकट्ठा करने की इनकी जो योजना थी वह बिलकुल सफल नहीं हो पाई। इसको इन्होंने पूरा नहीं किया। जब इन्होंने वित्त मंत्रालय में देखा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इनको अयोग्यता साबित हो चुकी थी, और उस कारण जो बदनामी इनकी होगी, उससे बचने के लिए किसी न किसी का दायित्व चाहिए तो दायित्व के लिए यह बकरा इन को मिल गया। इनके प्रति सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।

बैंकों के बारे में इनकी जब स्कीम आयेगी तब उस समय हम तफ्सील में बोलेंगे। लेकिन एक साल के बाद भी यह पता नहीं चलता है कि बैंकों के बारे में नीति निर्धारण का काम कौन करेगा? रिजर्व बैंक करेगा या नए बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज जो इन्होंने एक साल के बाद नियुक्त किए हैं वे करेंगे? इन्होंने एक बैंकिंग डिपार्टमेंट भी खोला हुआ है। जिस में नौकरशाह है और जिनको बैंकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार के लोगों से यह भरा हुआ है। ये लोग किस तरह के आदेश देते हैं? इस तरह के आदेश देते हैं कि वार्षिक बैठक के लिए प्रिंटिंग के ऊपर इतना खर्चा करना चाहिए। पहले अगर सवा रुपए में काम होता था तो नए आदेश के अनुसार तीन रुपए तक खर्च करने की इजाजत प्रिंटिंग के बारे में दी गई है। इस तरह के आदेश के बैंकिंग डिपाटमेंट के द्वारा दिये जा रहे हैं। अभी तक इस बात का पता ही नहीं है कि जिन बैंकों को हाथ में लिया है तो इनके साथ करना क्या है। हमने कहा था कि यह केवल एक राजनीतिक चाल है, इसको सोच समझ कर नहीं किया गया है। सोच समझ कर करते तो एक साल के बाद कम से कम कोई योजना तो बन जाती। लेकिन कोई योजना ही नहीं है। सोच समझ कर इसको किया जाता तो यह हालत इनकी नहीं होती।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): हमने तो पहले ही यह बता दिया था।

श्री मधु लिमये: हमने भी बताया था।

यह बात आपको माननी पड़ेगी कि जो बात मैं बैंकों के बारे में कह रहा हूं वह सही है और एक साल के बाद भी बैंकों के बारे में कोई योजना नहीं बनी है। साधारण जो लोग हैं, किसान हैं, लघु उद्योग वाले लोग हैं, खुद अपना काम करने वाले लोग हैं, सेल्फ एम्प्लायड लोग हैं, असल में इनको प्रचार का साधन तो खूब बनाया गया है लेकिन उनको कुछ मिला नहीं है। किसानों के बारे में भी आदेश यह निकाला है कि बड़ा ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्जा दिया जाएगा। अब आप देखें कि ट्रैक्टर खरीदने की शक्ति किन काश्तकारों में है, किसानों में है। हिन्दुस्तान में 75 प्रतिशत जो किसान हैं ये पांच एकड़ या उससे भी कम वाले किसान हैं। उनको बैंक क्या सहायता दे रहे हैं?

[श्री मधु लिमये]

वित्त मंत्री के नाते इन्होंने एक ऐसी चालाकी से अपना बजट पेश किया कि हमारे कुछ कम्युनिस्ट भाई भी बह गए थे। उस समय प्रधान मन्त्री ने कहा था कि मेरे बजट में जो नई कर योजना है उसके चलते कोई दाम नहीं बढ़ेंगे। हमने कहा था कि जरूर दाम बढ़ेंगे। आज क्या हो रहा है ? अकेले छः महीनों में आठ प्रतिशत थोक बाजार भावों में वृद्धि हुई है। ये प्रकाशित फिगर्ज हैं। एक साल के अन्दर पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। बीस जून से पहले वाला जो साल था उसमें पांच प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। साधारण लोगों को जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं उनके दाम तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष दिसम्बर में इन लोगों का जलसा हुआ था। इन्होंने समाजवाद की घोषणा की थी और कहा था कि ये नई दुनिया का निर्माण करने जा रहे है। इसके तुरन्त बाद जनवरी के शुरू में ही हमने क्या देखा ? दूसरे ही दिन हमने देखा कि एक जनवरी को बिड़ला को फर्टिलाइजर का कारखाना गोआ में स्थापित करने का लाइसेन्स दे दिया गया। उसी तरह से इस्पात और लोहे के दामों में इतनी ज्यादा वृद्धि की गई कि टाटा साहब ने भी इतने दाम नहीं मांगे थे। क्यों वृद्धि की ? आज लोहे और इस्पात के व्यापार में इतना काला बाजार चल रहा है कि उसका अनुमान करना भी आपके लिए मुश्किल है। लेकिन चूंकि हिन्दुस्तान स्टील में इनको बहुत बड़ा घाटा था, इसलिए दामों की वृद्धि इस तरह से हुई। आज उसका नतीजा साधारण लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बजट पेश करते समय इन्होंने कहा था कि मंहगाई नहीं बढ़ेगी, साधारण जनता के जीवन पर कोई असर नहीं होगा। ये सरकारी बयान थे। एनोनिमस स्पोक्समैन इस तरह के बयान दे रहे थे और आप अखबार निकाल कर इनको देख सकते हैं। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं ? तीन चार महीने के अन्दर अन्दर चारों ओर मंहगाई की ज्वालाएं भड़क उठीं। वित्त मन्त्री के नाते, बैंकों का सवाल हो, मंहगाई का सवाल हो, इनका जो सारा काम रहा है, उससे यह बिलकुल साफ हो गया कि वित्त मन्त्री बनने के पश्चात इन्होंने कोई बड़ा लोक कल्याणकारी काम वहां पर नहीं किया और जब यह देखा कि हम से नहीं हो रहा है तो मंत्रिमंडल की पुनर्रचना का बहाना बना कर यह दे दिया चव्हाण साहब के जिम्मे।

यह जो सत्ता का केन्द्रीकरण हो रहा है, उसके बहुत खतरनाक नतीजे निकल रहे हैं। इन्होंने बहुत से विभाग अपने हाथ में ले लिये है। हम जानते हैं कि ये बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारे काम इनको करने पड़ते हैं, इनको लोगों से मिलना पड़ता है, स्वागत समारोहों में जाना पड़ता है, विदेशी महमान आते हैं, उन से भी मिलना पड़ता है और विरोधियों की सरकारों को गिराने का भी काम इनको करना है, टापलिंग का काम भी इनको करना है। ये बहुत ज्यादा काम है और ये बहुत व्यस्त रहती हैं। इस सब का नतीजा क्या हो रहा है ? आज प्रशासन में दस पन्द्रह प्रतिशत काम ऐसा है जिस के ऊपर इनकी निगरानी रह सकती है। जिसका सत्ता की राजनीति से सम्बंध होता है। बाकी 85 प्रतिशत काम ऐसा है जिस की सत्ता आज नौकरशाही के हाथ में चली गई है। कैबिनेट सैक्रेटेरियट शक्तिशाली बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर सैक्रेटेरियट को तो मैं अदृश्य सरकार कहता हूं। ऐसे ऐसे लोग इस प्राइम मिनिस्टर सैक्रेटेरियट में है जो अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं लेकिन कम्युनिस्ट होते हुए भी ब्रिटिश इंटरनैशनल कार्टल के साथ भी दोस्ताना रिश्ता रखते हैं, जसे इम्पीरियल टोबैको। यह विचित्र देश है। इस देश में नाम के वास्ते कम्युनिज्म भी चलाओ और विदेशी पूंजीपतियों की जो बड़ी कम्पनियां हैं उन के साथ भी नाता रिश्ता जोड़ो।

श्री कंवर लाल गुप्त : कम्युनिस्ट पार्टी भी ऐसा कर रही है।

श्री मधु लिमये : मैं नकली कम्युनिस्टों की चर्चा कर रहा हूं ।

एक अदृश्य सरकार हमारे देश में स्थापित हो गई है जिसका किसी के भी प्रति दायित्व नहीं है, जो मनमाने ढंग से अपना काम करती है। प्रशासनिक सुधार के लिए पहले श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में और उनके मंत्री बन जाने के बाद श्री हनुमन्तैया साहब की चेयरमैनी में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिशन बना । सुना है कि चालीस लाख रुपया आपके ऊपर खर्च हुआ, क्या यह सही है ? इतना सब करने के बाद जो इनकी सिफारिशें हैं उनके ऊपर कोई सोच विचार और ठीक तरह अमल हो रहा है ?

मैं मानता हूं कि प्रधान मन्त्री व्यस्त रहती हैं । मैं यह भी मानता हूं कि सभी देशों के बड़े लोग अपने भाषणों को लिखने में, पत्रों को लिखने में दूसरों की सहायता लेते हैं । उस में मैं कोई बुराई नहीं मानता हूं । लेकिन जो भाषण हम देते हैं या जिन पत्रों पर हम हस्ताक्षर करते हैं, उनको कम से कम इतना देख तो लेना चाहिए कि उनमें क्या लिखा है और क्या हमने कहा है । प्रधान मन्त्री जो नवम्बर 1970 में रुड़की यूनिवर्सिटी में गई थीं । वहां इन्जीनियर लोगों ने सुना है कि इनका घेराव वगैरह किया था । उनको खुश करने के लिए इन्होंने एक भाषण उनके सामने दिया । उस भाषण में से एक ही अनुच्छेद मैं पढ़ना चाहता हूं :—

> "It is odd that the greatest doctors and engineers in the country who would be rated as the leaders of the profession and who assist the nation or add permanent asset to the nation can rarely hope to receive the pay or the status of Secretaries of Ministers. The brightest of youngmen and women choose engineering or medicine. If they happen to come in government they are very soon overtaken by the general administrator. This must change and I am trying to change it. The administrative system must reflect an individual's contribution to human welfare and economic gain."

लेकिन बाद में क्या होता है ? इस साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो इम्तहान हुआ, उस में श्रीमती अनुराधा मजुमदार नाम की एक लड़की पहले नम्बर पर पास हुई। प्रधान मंत्री ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने उस लड़की को अपनी ओर से शुभ संदेश और शुभेच्छा भेजी । लेकिन जिस संदेश पर उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया—उस का मस्विदा किसी आई० सी० एस० या आई० ए० एस० अफसर ने तैयार किया होगा,— उस में कहा गया है :

> "The Indian Administrative Service is the most effective instrument of doing good to the people of India."

उसमें इस प्रकार की बात कही गई है। वह कागज अभी मेरे पास नहीं है। प्रधान मन्त्री के रुड़की वाले भाषण और इस पत्र की आप तुलना कीजिए । 1967 में वह कहती हैं कि प्रशासन में जाने के बाद डाक्टरों, इंजीनियरों और दूसरे विशेषज्ञों की दुर्गति हो जाती है और उसको मैं बदलना चाहती हूं । मुझे अचम्भा होता है कि 1970 में विशन टंडन या किसी और आई०सी० एस० या आई० ए० एस० अफसर ने अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ लिख दिया, उस पर प्रधान मंत्री ने हस्ताक्षर कर दिये प्रधान मन्त्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रशासन के बारे में उनकी क्या नीति है । यह दो मुंह और दो जीभ वाली बात बन्द होनी चाहिए । वैज्ञानिकों, डाक्टरों, इंजीनियरों, विशेषज्ञों, कामर्स ग्रैजुएट्स और आडिटर्ज के सामने एक बात कह दी और अन्यत्र साधारण प्रशासकों की प्रशंसा में कोई दूसरी बात कह दी—गंगा गये तो गंगाराम और जमुना गये तो जमुनादास; यह बात नहीं चलेगी । प्रधान मन्त्री और सरकार को यह शोभा नहीं देता है ।

[श्री मधु लिमये]

एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्ज कमीशन ने पिछले वर्ष पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन पर अपनी रपोर्ट दी। मुझे आश्चर्य होता है कि जेनेरल एडमिनिस्ट्रेटर्ज को एकाधिकारशाही के खिलाफ उसने जो सिफारिशें की, उन के बारे में निर्णय लेने के लिए हमारी सरकार क्या करती है। उन दिनों श्री चव्हाण गृह मंत्री थे। मैंने उन से भी बातें कीं, लेकिन सब को अपनी अपनी चिन्ता पड़ी है। कौन प्रशासनिक सुधार की ओर ध्यान देता है? सब को यही चिंता है कि मैं कहां हूं और कल कहां रहूंगा। उन्होंने गृह मंत्रालय में एक विभाग खोला और उसके प्रमुख बनाये गए एक आई० सी० एस० अफसर, यानी जिस पर चोरी डकैती का अभियोग लगाया गया उसी को जज बना दिया गया। क्या यह कोई तरीका है? लेकिन मुखर्जी साहब को उस विभाग का प्रमुख बना दिया गया। उस के बाद एक सैक्रेटरीज की कमेटी बनी। उस में भी सब आई० ए० एस० के अफसर थे। वे लोग कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है प्रशासनिक सुधार की, आई० सी० एस० और आई० ए० एस० इतने अच्छे हैं कि वे सब काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं।

प्रधान मन्त्री के इन दो बयानों में कहीं मेल नहीं है कहीं सामजस्य नहीं है। जब तक इस बारे में कोई सुस्पष्ट नीति नहीं अपनाई जाती है, तब तक प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। भारत सरकार के तकरीबन 24,000 क्लास वन के अफसर हैं, उन में से 12,000 से अधिक विशेषज्ञ हैं, जिनको कोई मौका नहीं है। मैं श्री हनुमन्तैया साहब से जानना चाहता हूं कि क्या उन की कोई शर्त रहेगी कि अगर अमुक अवधि तक उन की सिफारिशों पर अमल नहीं होगा, तो वह इस्तीफा दे देंगे। (व्यवधान)

एक बात जरूर है। प्रधान मन्त्री की इस बात को मैं जरूर नोट करता हूं—और यह तारीफ की बात है—कि उन का दिमाग इतना लचीला है कि उन के पिता जी ने जिन लोगों को अपने से दस मील दूर रखा था, जिस डी० पी० मिश्र को उन्होंने दस मील दूर रखा था जिन हनुमन्तैया साहब से उन्होंने कोई नाता रिश्ता कायम नहीं किया था, आज वही प्रधान मन्त्री के आधार-स्तम्भ हैं। (व्यवधान) उनका दिमाग लचीला है। मैं यह भी मानता हूं कि उन में हिम्मत भी है। बाकी के इन लोगों में हिम्मत नहीं है। इसी लिए वह जीतती हैं। (व्यवधान)

अगर प्रधान मंत्री इस सत्ता का इस्तेमाल प्रशासनिक सुधार के लिए करतीं, तो मैं जरूर कहता कि यद्यपि सत्ता का केन्द्रीयकरण बुरी चीज है, लेकिन उन्होंने उस का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए किया।

जहां तक औद्योगिक नीति का सम्बन्ध है, हम को कहा जाता था कि श्री मोरार जी देसाई इतने बुरे हैं कि वह बड़े पूंजीपतियों को लाइसेंस देते हैं। (व्यवधान) खुद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है कि मैं तो देश को तेजी से समाजवाद की ओर ले जाना चाहती हूं, लेकिन श्री मोरार जी देसाई और श्री निजलिंगप्पा उस में रोड़े अटकाते है, उस में बाधक हैं। लेकिन कांग्रेस के विभाजन के बाद इस सत्ता का क्या इस्तेमाल हुआ? क्या यह सही नहीं है कि गोआ फर्टलाइजर के लाइसेंस के अलावा बिड़ला परिवार को चार नये लाइसेंस दिये जा रहे हैं : सौराष्ट्र, कैमिकल्ज, हिन्दुस्तान एलुमिनियम, ग्वालियर रेयन और बिहार में एक नया प्रकल्प? प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में और बम्बई कांग्रेस के बाद यह सारा काम हो रहा है। जब श्री मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे, उस समय जो लोग इस बारे में जोरों से चिल्लाते थे, जिन में हमारे कुछ नकली वामपन्थी भी हैं, आज वे बोलने के लिए तैयार नहीं हैं; क्या मैं इस नतीजे पर पहुंचूं कि अगर कोई काम एक व्यक्ति करता है, तो वह खराब है लेकिन अगर वही काम, या उससे भी बदतर काम, कोई दूसरा व्यक्ति करता है, तो वह अच्छा है, या कम से कम चुप्पी साधने वाला काम है? (व्यवधान)

आज कम्पनी विभाग श्री रघुनाथ रेड्डी के हाथ में है। उन पर मुझे दया आती है। उन का एक मात्र काम यह रह गया है कि प्रधान मन्त्री चुनाव के लिए राजनैतिक चन्दे के लिए जिन कम्पनियों से दोस्ती रखेंगी, उन कम्पनियों को वह क्लीयरेंस दे दें। कल राज्य सभा में इस बारे में चर्चा हुई। आज दोपहर मैंने उनकी कार्यवाही पढ़ी। मैंने देखा कि वह एक प्रश्न का भी साफ जवाब नहीं दे पाये। वे सवाल श्री कृष्ण कान्त और श्री चन्द्र शेखर द्वारा पूछे गये थे, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, मेरी पार्टी के लोगों के द्वारा नहीं। आज जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनका वामपन्थी दिमाग है, उन्हीं लोगों से यह गंदा काम करवाने के लिए श्री रघुनाथ रेड्डी को कम्पनी विभाग का मंत्री बना दिया गया है।

विदेश व्यापार विभाग श्री ललित नारायण मिश्र के हाथ में है। सारा सदन जानता है कि वह कितने काबिल और योग्य आदमी हैं। (व्यवधान) उधर के बड़े लोग आ कर मुझे कहते हैं कि श्री ललित नारायण मिश्र को विदेश व्यापार विभाग का मंत्री इस लिए बनाया गया है कि उन के जिम्मे प्रधान मन्त्री ने यह काम सौंपा है कि इस साल के अन्त तक चुनाव के लिए पांच करोड़ रुपया इकट्ठा करो।

भारत नेपाल व्यापार के बारे में तीन चार साल से मैं बोल रहा हूं, पश्चिमी किनारे पर जो तस्करी चल रही है उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। हमारे दोस्त और साथी बोल रहे हैं। कई अर्थ-शास्त्रज्ञों ने आंकड़ों से यह साबित किया है, प्रोफेसर बी० आर० शेणाय और दूसरे लोगों ने कि तस्करी कम से कम 6 सौ करोड़ रुपए की हो रही है। जो रुपए की बाजार में, खुले बाजार में या ब्लेक-मार्केटिंग में कहिए, दर है उसी से पता चलता है कि अवमूल्यन के बाद भी रुपये की स्थिति सुधरी नहीं है और कैसे सुधरेगी? जब 600 करोड़ रुपये की तस्करी होती रहेगी तो रुपये के ऊपर दबाव रहेगा और मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि इस तस्करी को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो रुपये के अवमूल्यन का प्रश्न ले कर फिर यह सरकार आएगी। इंदिरा गांधी की सरकार को मैं अवमूल्यन की सरकार कहता हूं। 1966 में उन्होंने अवमूल्यन किया रुपये का ··· (व्यवधान) प्रधान मंत्री बच जाती है और अशोक मेहता साहब ही रह जाते हैं? अशोक मेहता तो जिम्मेदार हैं लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी किस की है यह भूल जाते हैं?···

अध्यक्ष महोदय : पचास मिनट आपके हो चुके हैं।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इतना टोका जाता है मुझे कि बहुत सा समय उस में निकल जाता है। आप को घन्टी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कुछ मुद्दे अपने कम करूंगा और जल्दी खत्म करूंगा।

तो 600 करोड़ रुपये की तस्करी चल रही है। नवम्बर 1968 में भारत नेपाल व्यापार के बारे में बलिराम भगत एक करार कर के आए जिस में नेपाल ने कहा कि 80-90 लाख रुपये का सिन्थेटिक फेब्रिक्स हम भेजेंगे। 1 करोड़ 20 लाख रुपये का स्टेनलेस इस्पात भेजेंगे, इससे अधिक नहीं भेजेंगे। आत्म नियंत्रण रखेंगे। लेकिन क्या आत्म-नियंत्रण हुआ? मैंने आंकड़ों से साबित किया है कि कलकत्ते के बन्दरगाह पर जितना सिंथेटिक फेब्रिक आया है वह उससे कहीं ज्यादा है। एक किलोग्राम में कम से कम 14 मीटर कपड़ा होता है। मैंने साबित किया कि आत्म-नियंत्रण के करार में जितना कपड़ा भेजने का वायदा किया था उस से कम से कम तीन चार गुना कपड़ा वहां बन रहा है और नेपाल में तो कोई मण्डी है नहीं वह भारत को भेजा जा रहा है। अब यह करार समाप्त हो गया है। मुझे पता चला है कि श्री ललित नारायण मिश्र ने एक नया सुझाव दिया है चन्दा एकत्रित करने के

[श्री मधु लिमये]

लिए कि स्टेटस-को आगे चलायेंगे। उस की क्या जरूरत है? उस समय तो आप कहते थे कि···

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल०ना०मिश्र): यह बात मत करिए। हम ने कोई सुझाव नहीं दिया है।

श्री मधु लिमये: अध्यक्ष महोदय, यह आते ही इतना गरम क्यों हो गए? अपने लिये लिया था, यह तो नहीं कहा मैंने। मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं किया।

तो मैं भारत नेपाल सन्धि के बारे में कह रहा था। उन दिनों में इन की दलील थी कि चूंकि सन्धि है और उसकी जो परिभाषा है वह संदिग्ध है, ऐम्बीगुअस है, इस लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब तो करार की अवधि खत्म हो रही है न इस साल? अब नई संधि मत बनाओ। नेपाल से कहो कि विदेशों से जो माल आप लाते हैं और विदेशी कच्चे माल के ऊपर जो माल आप बनाते हैं, मैं ने कई उदाहरण दिये, रेडीमेड गारमेंट, और मैंने बलि राम भगत को दशहरे का एक प्रेजेन्ट भी दिया, बम्बई के बाजार से खरीद कर मेड इन नेपाल लिखा हुआ लेकिन जापानी शर्ट था और उन्होंने माना कि आप ने बड़ी हमारी मदद की, मैं उन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार नेपाल वालों से यह कहे-पड़ौसियों से अच्छा रिश्ता मैं भी चाहता हूं, लेकिन नेपाल में कुदरती तौर पर जो कच्चा माल होता है हाइड्रो एलेक्ट्रिक रिसोर्सेज हैं, जंगल का सामान है, पेपर फैक्ट्री लगाने में, जंगल के सामान का माल बनाने में आप उन की खूब मदद कीजिए मैं उस का विरोधी नहीं हूं मैं नेपाल का मित्र हूं लेकिन नेपाल में जो बदमाश भारत के हो लोग हैं और जो बड़े धार्मिक लोग हैं, चीटियों को शक्कर भी खिलाते हैं और इन्सान की गर्दन भी काटते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप नाता रिश्ता मत जोड़िए। आप नेपाल से कहिए कि आप के देश में जो कच्चा माल होता है और आप के देश के नौजवानों को काम मिले इस के लिए पड़ौसी के नाते हम अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हैं लेकिन तस्करी को प्रोत्साहन देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। चुनाव के लिए मैं जानता हूं कि आप को पैसा इकट्ठा करना है। सभी दल कम या अधिक मात्रा में करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय हितों का बलिदान कर के यह काम नहीं करना है।···(**व्यवधान**)····अरे, हम को कौन देता है? हम को देने की बात कहां आती है जब हम इस तरह का भाषण करेंगे तो कौन हम को देगा?

तो मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय हित को होम कर के, उसको जला कर क्या आप अपनी दलीय राजनीति करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, कम से कम मैं यह जानता हूं कि यह सरकार समाजवादी सरकार नहीं है न समाजवाद की स्थापना करने वाली है, लेकिन कम से कम हम मानते थे कि कुछ चीजों के बारे में इन का दिमाग साफ होगा जैसे विदेशी कम्पनियां बनाम देशी कम्पनियां। इन को समर्थन देना चाहिए देशी कम्पनियों को। मैं समाजवाद की बात नहीं कर रहा हूं उसी तरह जो एकाधिकारशाह लोग हैं उन की वनिस्वत स्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए, जो बड़े लोग हैं, उन के मुकाबिले छोटे लोगों की मदद करनी चाहिए। इसमें तो बहुत बड़ी समाजवादी सिद्धांत की बात नहीं है? लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि विदेशी कम्पनियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इम्पीरियल टुबेको कम्पनी का मामला है। बहुत अरसे से लिख रहा हूं। मन्त्री महोदय ने माना, श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने माना लेकिन पत्र क्या लिखते हैं कि—सिगरेट मेकिंग इज ए कॉटीन्युअस प्रोसेस इंडस्ट्री। एक मिनट में सिगरेट का कारखाना बन्द कर सकते हैं और खोल सकते हैं मैं जानता हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र में इम्पीरियल टुबैको कम्पनी है। ग्लास-फर्नेस है, रौटरी किल्न्स है (**व्यवधान**) अरे इण्डियन नाम के वास्ते हो

गया और पी० एन० हाक्सर के भाई उस के चेयरमैन बन गए, लेकिन शेयर-होल्डिंग किसकी है ? तो आप हिन्दुस्तानियों को बढ़ावा दीजिए, विदेशियों को बढ़ावा न दीजिए और कानून तोड़ कर वजीर सुल्तान अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है तो आप दण्डित कीजिये उसे ।

इसी तरह अध्यक्ष महोदय, जो एकाधिकारशाही वाले लोग हैं, कई ऐसे उद्योग हैं जिस में एकाधिकार उन का है । कई दफा मैंने यह साबित किया है । मेरा ख्याल है, एक केमिकल फर्म के बारे में बात थी कि जो दिखाया हुआ दाम है और जो बाजार में है उस में बीस-बीस गुना का फर्क है । क्योंकि एकाधिकार है । तो जहां जहां यह है वहां आप को चाहिए कि नये लोगों को मौका दें पैदावार बढ़ाने की दृष्टि से और बड़े और छोटे का जहां सवाल आए वहां आप हमेशा छोटों को आगे बढाने की कोशिश करें । इतना भी आप नहीं करते हैं तो क्या मतलब है समाजवादी घोषणाओं का ?

मैं एक ही बात कर समाप्त करता हूं । यह इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जो नई नीति है इस के बारे में स्टेटसमेंन में खुलासा आया कि निर्यात प्रोत्साहन के नाम पर जिन बड़े लोगों को आप ने मना किया था जिस क्षेत्र में उस में भी निर्यात प्रोत्साहन के नाम पर आप ने दरवाजा खोल दिया । निर्यात प्रोत्साहन का अर्थ क्या है ? कि यह कम्पनियां निर्यात तीन साल की अवधि में करें । मतलब चुनाव तक पूछने का सवाल ही नहीं, तीन साल तो टल गये । तीन साल के बाद कोई कुछ करने वाला नहीं है । उस के बाद कहेंगे कि हम क्या करें, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया । एक सुझाव यह भी आया है कि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के जिम्मे यह करें । तो यह लोग कानून तोड़ कर पैसा कमायें और आप उन की एक्सपोर्ट प्रमोटिंग एजेन्सी बन जायें । यह नयी पालिसी है आप इस सदन में यह आश्वासन दे चुके हैं कि ऐसे क्षेत्र में जहां स्वदेशी विज्ञान और तकनीक काफी मात्रा में विकसित हो गया है, हम विदेशी सहयोग की घूट नहीं देंगे । बिस्कुट के लिये, आइसक्रीम के लिए ब्रैंजियर्स के लिये हम नहीं करेंगे । लेकिन हम देख रहे हैं खुद उद्योग मंत्री लिखते हैं कि बीयर के क्षेत्र में हम ने विदेशी कोलाबोरेशन को मान्यता दी है । क्यों दी है ? अगर यह एकाधिकारशाही है तो नए लोगों को मौका दो, एकाधिकारशाही को तोड़ो, लेकिन यहां की एकाधिकारशाही को खत्म करने के लिए विदेशियों को न्यौता देने का क्या मतलब है ? पैदावार बढ़ाने के लिए कोई नीति नहीं है । इस लिए, अध्यक्ष महोदय, सत्ता के केन्द्रीकरण से कई खतरनाक नतीजे निकल रहे हैं । मैं कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं उठा रहा हूं, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौकरशाहीकरण बढ़ता चला जा रहा है, लोकतन्त्र के लिए खतरा पैदा हो रहा है । इस लिए अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण खत्म करते हुए सदन से अनुरोध करता हूं कि जो बातें मैं ने यहां पर रखी हैं, उन पर ठन्डे दिमाग से सोचें और इस प्रस्ताव का साथ दे कर इस केन्द्रीकरण और लोकतन्त्र विरोधी खतरे से बचायें ।

15 hrs.

MR. SPEAKER : Motion moved :

> "That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers.".

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : I support the motion of no-confidence that has been so ably moved by my hon. friend Shri Madhu Limaye. He has virtually covered all the field, and the charges that have been levelled by him in regard to rigging up in elections are hundred per cent correct. For, today, there are two State Assemblies which are in dissolution. One is the Kerala Assembly and the other is the Manipur Assembly. The Kerala Assembly was dissolved in the month of May, while the

[Dr. Ram Subhag Singh]

Manipur Assembly was dissolved last year soon after the Prime Minister visited that place, when her meeting was not allowed to be held and when she got bulleted the poor Manipurians there. But this shameless Government does not know that it should apply a uniform policy in these two States.

We do stand for elections. You may hold elections wherever you like. It is good that you are holding elections in Kerala. But where is your face, the face of boldness, in Manipur? Why do you not immediately order for elections there ? Therefore, I charge the Election Commissioner also. He should see that the two elections are held simultaneously, because the Manipur Assembly was dissolved much earlier as compared to the Kerala Assembly. Therefore, this is a dishonest action of this Government of India. Since the Prime Minister is holding the portfolio of Home Affairs also. I charge her of dishonest dealings in Kerala and Manipur.

Again, what is the good of maintaining the West Bengal Assembly ? Are you going to pay them gratis ? You are maintaining a horde there. What for ? For advising an incompetent Governor who knows nothing and who goes on abusing everybody. Therefore, I say that she should immediately, if she has any honest feeling left in her mind, dissolve the West Bengal Assembly also.

AN HON. MEMBER : None left.

DR. RAM SUBHAG SINGH : I accept that she has none.

I have no quarrel with anybody. But what about the election affairs ? Shri Madhu Limaye quoted certain figures and he gave the percentage also. The total number of voters in Kerala in 1967 was 86,41,296, and the number of service voters was 20,791. But the number of voters included after intensive revision comes to 31,66,459, and the number of voters deleted after intensive revision was as follows,— I do not know where that intensive business is. Was this government kept in power only to do this intensive work ? They got deleted 17,62,916 vaters. Can you find any sense in this ? Where is the Family Planning Minister ? How many people are born and how many people die ? He should give those figures. He got himself dismissed, and dismissed after continuing unnecessarily for six months more. Another person is in charge now but he is not traceable perhaps at this moment.

So this is the big bungling that is going on. I do not want to go into details because they have been gone into by Shri Madhu Limaye. But I make this demand : If there is any sense of honesty left in this Government—I do not believe there is—they should immediately order an inquiry ; they should immediately appoint a Commission of Inquiry to investigate the correctness of the voters' list. You, Sir, have contested elections so many times, both to the State Assembly as well as to Parliament. You know that all parties are supplied with the voters' list. I ask the Election Commissioner, where is the voters' list ? I ask the Prime Minister to place that list on the Table. But there is no voters' list available.

AN HON. MEMBER : Tomorrow.

DR. RAM SUBHAG SINGH : Not tomorrow but today when the session is on.

Therefore, this is the bungling that is intentionally got done by the Government of India headed by the Prime Minister.

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : Intentionally ?

DR. RAM SUBHAG SINGH : The Chairman of the Administrative Reforms Commission is laughing ; he is now elevated to Cabinet and has become Law Minister. He had given a threat 'I will not dissolve the Administrative Reforms

Commission unless and until I am elevated to the Cabinet'. I congratulute him on his threat having worked and getting his recommendations implemented.

He comes from very near Kerala, Mysore. In Kerala, he knows that the rainfall is about 100 inches annually. Rain is heavy particularly during these months. This morning we were here when a Calling Attention motion was answered by the Minister of Irrigation and Power. When Shri Tapuriah asked a question about villages being washed away and more than two dozen vehicles drowned, it was clear that no warning system was traceable. Defence personnel also live there ; the State Government personnel are also there. But nobody gave any warning.

What is the rainfall in Kerala ? It is nowhere less than 100 inches. During this time, in August, if you go from Cannanore to Trivandrum, rarely there will be a day without rainfall. Can you satisfactorily carry on the election campaign there ? If not, is it going to be a fair and honest election ? I do not say 'do not hold the election,' but apply the same principle everywhere. Wherever the Assembly under dissolution—I would request Shri Hanumanthaiya, now that he is the Law Minister, at least not to give dishonest advice, as he did previously in regard to Kutch and other matters to Government—Wherever the Assembly has been dissolved, election should be held. But in the case of Kerala only, they got this order issued. It was announced over the radio that election would be held on the 17th September. The Election Commissioner says, 'If anybody wants to submit a list of voters whose names are not recorded, I can extend the date by one or two days'. Is this justice in India ? Can everybody hear this announcement ? Though of course, Kerala is a very literate State, can everybody whose name is not there go from his house and get his name registered in the panchayat register and get the electoral list corrected in time ? If it is not possible, this is called rigging the electoral rolls and no amount of argument is going to convince anybody, because even now no party has been supplied with a printed copy of the electoral roll to an election scheduled to be held so soon, on September 17, much less district parties or tehsil parties.

Now, I come to the concentration of power, because this is one thing which must be ended in India. I have no grouse against anybody, but I would like that the Cabinet must function as a Cabinet. It should not fuction in a style in which this feudal system functions, because these days negotiations are being carried on with the former Rulers, only with a view to get their votes on this no-confidence motion. Had there been any sense of truthfulness, they would not have moved that Bill to delete that article in the Constitution. If you want to delete it, delete it completely, we have no grouse against you, but now you have started haggling, just as you were haggling with Tatas for the Mithapur project, just as you were haggling with the Birlas for the Gandhi National Memorial, with Kamanis and the drug manufacturers, petroleum manufacturers and others. Can you say that dozens of deals were not effected for giving licences to these persons ? I want a correct reply. If you felt that no licence should be given to Tatas, what led you to give it ? Were your hands not warmed with a view to giving that licence ? Licence after licence is given to monopolists.

Where is your land reform ? You said land reforms would be effected whithin this year. Where have you got it done ? In West Bengal you are in complete control, with your own friend as Governer. Get it done there. You have got an allied Government in Bihar, why don't you get it done in Bihar ? You have got an allied Government in U.P., why don't you get it done in U.P. ? Everywhere there is confusion.

Here in Delhi you apply this Monopolies Act, you get the urban property confiscated. Bombay, Calcutta etc., are there, but start with Delhi, this is under your own feet.

You get the power concentrated into

[Dr. Ram Subhag Singh]

your own hands by taking over the Home Ministry. I have every respect and regard for all the Ministers, but now they are shorn of their wings. How can Chavanji control his revenue intelligence ? How can electronics be controlled by Shri Jagjivan Ram when it is controlled by you ? Somehow or other he saw to it that his Ministry was consolidated. But you keep electronics, can you handle it ?

I am asking a question. What is this that you are doing ? This is the age of the people. Power must be given to the people, but now you are giving it to your own kith and kin, your own bureaucrats, because you come from an aristocratic family, because the people who run the Secretariat, who are going to control the Secretariat, are the Private Secretaries. This is the Private Secretary raj in India, and we want to dash it to pieces—this Private Secretary rule. Haksar, Kashmiri rule. We do not want to be a colony of Kashmir.

What is going on in Kashmir ? Mr. Speaker, it is nearer your home town. Even Bakshiji says that about 250 villages have been burnt. How have they been burnt ? You negotiated with all the leaders of that area, and 250 villages are burnt. It is not a small number. How many people have been rendered homeless, how many processions were brought against you, how many black flags were there in the streets of Kashmir ? You can say there were many admirers, I know that, because the Kashmir Government knows only that business, they entertain fully, and both Sheikh Abdullah and Shri Bakshi went, and now Shri Sadiq will also go because he has no roots, because 250 villages have been burnt in Kashmir during two or three months.

Therefore, I say that this concentrarion of power is ruining the country, it is depriving the people of India of this principle that the Government should be of the people, by the people, for the people. Now it is the Government of aristocrats, by the Private Secretaries, for the Private Secretaries, because he cited names, where those people are.

I ask : how can you defend if the Chinese invade you, because on the 20th the floods came, and on the 23rd it was announced, while your movements are announced immediately. If there is something in Safdar Jung, the AIR is there prior to the incident. If there is invasion or intrusion in Bhutan nobody knows where there was intrusion. This is the standing example of your inefficient, incompetent and unindian administration which you are giving to this country. Chavanji, while he was in Bombay got a good tamasha organised in the shape of the ruling party in December; I congratulate him on that. What has happened to it ? In that tamasha you decided about the nationalisation of sugar industry in U.P. and Bihar. Later on Jagjiwan Ram Babu deleted Bihar from it. What about U.P. ? How many tonnes of money have poured from the industrialists for this nationalisation ? What has been done ? I want them to implement honestly their own decisions. If there is anybody who is not allowing you to nationalise it, get hold of him through your private Secretary because they can function. Now they say it is a shuttling business between Lucknow and Delhi. Some say it is being done in Lucknow; some say it being done in Delhi. Has the new Law Minister prepared a note using his knowledge of the ARC to nationalise all things that exist in India ?

Then about the communal riots during this regime. I charge that the Prime Minister has hoodwinked this nation and that she has managed to get more Muslims and more Hindus killed in India during her regime due to the incompetence of the State Governments. Why don't you dismiss the State Governments wherever they may happen ? You could have got the Gujarat Government dismissed ; I do not mind it. What about Maharashtra ? What about Bihar ? You should do that immediately. What happened to the decisions of the National Integration Conference ? Due to the action of the Government more and more riots have been taking place. In Bhiwandi it was known to the people ; in Jalgaon it was known to the people. Those poor

Muslims and poor Hindus got killed. Where was your CRP ? What was your Government doing when poor Muslims were killed in Chaibasa ? Nothing was done there. Later they go there to shed crocodile tears and unnecessarily expend the tax payer's money and do nothing afterwards. It was announced that something concrete would be done. I want to know the concrete steps that were taken to give equality of status to all the citizens of India. Have they done anything ? If steps are even informative stages, steps to guarantee to the citizens of India that nobody would touch a person even though he happens to belong to a minority community, that he will get all the constitutional guarantees that are there be they Hindus, Muslims, Sikhs or Isais, all the people who inhabit this country, I shall be happy.

Then there is the refugee problem. It is due primarily to the statement made by the Prime Minister and circulated through her own agencies, foreign, agency, that bad name had been brought to our country. While coming from Banaras I was reading a local Hindi daily and in that paper her own alley, a member from the BKD has written an article. He says that he discussed with her this problem and he mentioned a poster in which the important points of the Prime Minister's speech were mentioned. They were all against India. What is the good of charging Pakistan if, by your own action, you are introducing or creating confusion in Pakistan ? You have to be condemned. What about Farakka ? You have got your boneless Ministers, because they have got no guts. They do not know what to do. It was in Farakka. Now, you are going to create the same trouble. Here, what has been done ? Pill-boxes were constructed just in your field. Pill-boxes were created, constructed, due to this very Minister and the engineers. There perhaps that might have happened during Nandaji's time. Now, regarding this Farakka business, they have come right under Russian pressure, and Pakistan will get water from Farakka. Is it in India's interest to give water to Pakistan from Farakka ? Then, who compelled it ? What was the business of your Foreign Ministers in this matter ? Of course, you will deny, I Know. But do you understand what is the complication? If you do not understand, then why don't you take the advice of the people of India ? Why don't you agree to send your Ministers to take the advice of the people who inhabit that particular area of Pakistan ? You would not do it, because you have no faith in the people. When you visited Calcutta, you drove straight to the AIR station. You had no time to go and see the refugees. The result is that more than two lakh people have come here. We all expected that all arrangements would be made to give them succour, but then nothing has been done. Neither any Muslims should be uprooted from India nor any other minority should be allowed to be uprooted from Pakistan. India is the home of all the people who inhabit it. Similarly Pakistan must treat all the people who inhabit Pakistan, be it West Pakistan or East Pakistan. But you are so utterly incompetent that you are not in a position to get that done.

I have one example regarding this satellitism in foreign policy. There is the International Control Commission ; they do not know what is being done where. You do anything, any correct thing ; you might favour any particularism ; I have no grouse. But why are you bringing bad name to this country by becoming the colony of a foreign country ? Therefore, I want that India must have a Government which represents the urges of the nation, the urges of the people of India, and their aspirations. You do not represent their urges and aspirations. If you represent anything, you represent corruption ; you represent incompetence ; you represent cliquism ; you represent disintegration, and you represent everything that is evil for India, and so you have got to go.

Therefore, I support this motion, and I want that this Government should be kicked out.

SHRI M. R. MASANI (Rajkot) : Mr. Speaker, Sir, first I should like to start by explaining why this morning my collea-

[Shri M. R. Masani]

gues and I did not stand in support of the admission of this motion. That attitude arises from the conclusion to which we came as far back as about two years ago that these motions of no-confidence moved at the opening of every session have become very sterile, routine things; not only that; they become self-defeating, because having challenged the Government on the opening day and, almost inevitably taking a defeat, the whole of the rest of the session tends to become something of an anti-climax. I believe that this is bad parliamentary strategy, and therefore we certainly do not want to take part in the responsibility for following this path. But, Sir, the motion has been admitted by the House, and now it becomes necessary to go into its merits.

Mr. Madhu Limaye gave three grounds for his motion. The first is the Kerala situation. I do not think I shall deal with it, because those who have spoken already have dealt with it to some extent. I am quite prepared to listen to both the warring groups of Communists giving up diametrically opposite facts from which we will have to choose. I would rather save my time and turn to other matters.

The second ground given by Mr. Limaye is a good one—concentration of power. I am very glad to find that so many gentlemen on both sides of me have now become aware of this concentration of power. One would imagine this is the first time it has happened. It is not. This concentration has existed for twenty years and has been slowly increasing year by year. It is part of the system or economic theory which they have adopted the system of State Socialism. If anyone believes that State Socialism can co-exist with decentralisation of power, I think what has already happened and what is going to happen will provide some useful education to those who have not been able to see things already. Acharya Vinoba Bhave mentioned concentration of power in five or six hands in Delhi ten years ago. It is not very important whether it is five hands or ten hands or two hands. It is bad if the number of hands gets smaller and smaller. But concentration of power in even five or ten hands in Delhi for the whole of India is bad enough. I am very glad that this greater awareness is coming over all of us. I am glad that Mr. Madhu Limaye has drawn attention to it.

Undoubtedly the importance given to the Intelligence Services of various kinds in the Cabinet reshuffle that took place recently did draw a lot of attention. It was out of place. Prime Ministers of democratic countries have not shown any interest in the Secret Service or secret police. That interest is shown by fascist and communist dictators. It is a great pity that the Prime Minister of this democratic country should have shown so much interest in a subject which should have been left to an underling.

The other point that Mr. Limaye makes is even more valid bureaucratisation of administration. Quite right. I am glad he has now come to realise that State Socialism must end in bureaucracy. When you hand over power to the hands of officials big and small in place of free citizens, whether you like it or not bureaucratisation sets in. You cannot have State Socialism, you cannot have nationalisation and then Complain of bureaucratisation sets in. You cannot have State Socialism, you cannot have nationalisation and then complain of bureaucratisation. It is an inevitable price you have to pay. If we do not want bureaucratisation; let us join intelligent socialists in other parts of the world and realise that nationalisation, State industry and State enterprise are not the best way to social justice. There are other paths which are faster and more effective. I very much welcome the fact that a radical socialist like Mr. Madhu Limaye has realised that bureacracy is setting in. If I may say so, he will have to re-think a little more. Dr. Lohia was a pioneer in that thinking. Let us give credit to him. He was an old friend of mine. He saw that State Captalism which are practising in India in the name of Socialism is as reactionary as any other kind of capitalism could possibly be. Therefore, he moved away from one camp as from the other. I am very glad that Mr. Limaye, by including this point in his grounds for the no-confidence motion.

is carrying on the work of educating the people.

There is nothing new in all this. Gandhiji had sensed it. Gandhiji said long before Swaraj came that Swaraj must not mean the replacement of the white bureaucrat by the brown one. This is exactly what Swaraj today under this regime has come to mean-replacement of a white bureaucracy by a brown bureaucracy. Therefore, for these two reasons we support the motion. But the reasons why we shall vote for this motion, because we shall, are much broader.

We believe that the totality of this Government's domestic and international policies is disastrous for this country. We believe that everything or almost everything they do is hurting the couutry's vital national interests. Take their economic policies. Ever since the disastrous Second Plan devised by Dr. Mahalanobis and his communist colleagues from Russia, Poland and other countries at the Institute of Statistics in Calcutta was imposed on this country. the economy of this country has gone down from bad to worse. The Second Plan Frame was imposed on the Third Plan, which also became a failure like the Second. And the Fourth Plan which we are undergoing today is nothing but a magnified version of the Mahalanobis Second Plan which has brought this country to ruin.

The fiscal policies of government, putting aside the Plans a moment, are equally bad. On the one hand, there is excessive taxtion, both direct and indirect, and on the other hand there is the constant resort to inflation. Many of us have warned the Government of the time of the last Budget and the Budget before, that their measures were inflationary and would result in rising prices. Shri Madhu Limaye gave the figures. In spite of all their protestations, a price rise as forecast by us has taken place and I predict it will take place further.

So I was very sorry for Shri Chavan, when I read the Cabinet reshuffle picture as it has emerged, He is the fall of my; he is the man who has been put on the spot. Because let me tell him that, unless he changes radically and fundamentally the polices of his government, those policies, the fiscal policies and the planning policies are going to doom this country and its economy to greater and greater depression. There is going to be a continual rise in prices, there is going to be greater and greater unemployment during every year that we pass, there is going to be increasing misery for the people, and I do not rule out ultimately food shortage, starvation and famine in this country. This is the pat of ruin that this government is following and Shri Chavan has taken up the stewardship just when the ruin is becoming more and more visible, more and more inevitable. This is one reason why this Government must go and should not be allowed to survive.

The other reason is political. All the home and international policies of this Government reek of the subservience to the Soviet Union and the dictatorship there. The foreign policy of the present government is one of complete satellitism to the Soviet Union. I would like the Prime Minister to tell us of any single major issue on which she has taken a position contradictory to that of the Soviet Union. I do not think even one such instance exists. Whether you go eastwards to Cambodia and Vietnam or westwards to West Asia and Czechoslovakia, the result is the same, complete subservience to the Soviet line. May I reall that in this very House when Shrimati Sucheta Kripalani—I am glad she is sitting on our side now—when she was a member of the Prime Minister's party and moved a simple resolution condemning the brutal Soviet attack on Czechoslovakia, the Prime Minister refused to accept that amendment and got it defeated. That is why I say that the entire foreign policy of this government is one of satellitism to the Soviet Union.

The latest example of this, of course, was the impropriety and breach of diplomatic and international law which was perpetrated when Naxalite No. 1 from South Vietnam was entertained in this country as the guest of our government. What would we feel if a Naxailite from

[Shri M. R. Masani]

Bengal were to be received in a country with which we are friendly and was entertained as a guest of their government? So, I would say that the entire range of the Government of India's international policy is one that does no credit to the independence and sovereignty of our country.

Simultaneously, at home there is the consistent infiltration of Communists and crypto-Communists in key positions in every walk of life.

The continued sufferings of the people of Bengal is perhaps the worst evidence of this trend. When the Communist-dominated government of Bengal was removed and President's rule came, the people of Bengal naturally heaved a sign of relief. They felt that at last some relief was coming their way and their rights and liberties would be safe. Nothing of the kind has happened. I have visited Bengal more than once and I have talked to numerous people from all walks of life. All there, are in argeement that violence has not abated, that terrorism is still there and as far as Naxalite violence is concerned, it is probably even worse than it was under Shri Jyoti Basu! Now, how does this happen? Obviously, New Delhi is primarily to blame,. President's rule means rule by the Home Ministry. Of course, the instrument through which you rule is the Governor and the Governor there is such a person that no one could be considered to be more unfit to be the Governor of Bengal at this juncture. Today even the Prime Minister's own party in Bengal has demanded his recall.

Sir, there is no reason to be surprised if Shri Dhavan has proved to be the kind of Governor that he is. The entire responsibility is that of the Government. In this house on the 23rd of December 1967, when the Prime Minister was exactly where she is sitting now, I related to her the record of Shri Dhavan, whom she had then appointed as High Commissioner designate in England.

I had read out the whole record then; I will not do so now. It is in the records of Parliament of the 23rd December, 1967. I had suggested that that gentleman was unfit to represent this country in Britain. I shall now repeat only one quotation from Shri Dhawan to show how utterly unfit he was later on to be appointed Governer of a State when Communist infiltration was going on, when an attack on India's security and unity was in force, when people who owed allegiance to Mao Tse-tung were functioning.

What did Shri Dhawan say when our neighbour, Tibet, was overrun by the Chinese? This is what he said in the *National Herald* then:-

> "The interests of India are not directly involved, and the question of our making a protest simply does not arise. The propaganda about Chinese 'aggressson' in Tibet is completely baseless."

Then he went on to explain what happens in his view when Communits take over a part of Asia. This is very crucial. He went on to say:—

> "I have no doubt that the people of Tibet will benefit greatly as a result of closer contact between Tibet and China. Tibet is one of the most backward coutries in the world... All this will change under Chinese rule. Tibet will now share the benefits of civilisation like all the other countries in the Central Asia which have passed under Communist rule."

It was exactly predictable if such a persons, holding these views, were to be made the Governer of a State where the Chinese "front paw," as Mao Tse-tung put it, had landed on our territory, what should happen. Was this the man who was going to resist this infiltration and attack on our sovereignty and unity or was he going to say that the poor people of Bengal will also come to enjoy the "benefits of civilisation" when Mao Tse-tung through the Naxalites takes over the State.' The entire guilt lies on the gentleman and the lady sitting opposite who, in spite of all

these warnings, appointed this man, the most unfit in India, to be the Governor of Bengal at the present juncture.

There can be no question of elections in Bengal. There can be no question of going to the people until the people of Bengal are freed from the terror under which they are living. My Party has no hesitation in saying that until the communist Parties in Bengal are outlawed, the possibility of a free election does not exist.

That is why, for all these reasons, we believe that this Government is a danger to the security of our country, that it should go and, therefore, we shall vote for Shri Madhu Limaye's motion.

We want a change of Government, but there are ways and ways of changing the government. There is a democratic way of changing the government and there are some doubtful ones. The undemocratic way of changing the government has been practised in many countries. It was practised in Britain in the days of Sir Robert Walpole, who was a very corrupt Prime Minister, who bought up members of the Opposition and who said that "every man and woman has a price." It happened in the Fourth Republic of France where, with constant defections, France came to have no stable government until the people of France turned to DeGaulle and instituted him as President with superpowers which were not there under the Constitution. This has been happening in our country and we call it "toppling". It is a rather indecent game which we have invented.

"Toppling" has nothing to do with democracy. That is not the way in which self-respecting people come to power. Democratic people come to power after an appeal to the people and a mandate of the electorate in the way that Mr. Ted Heath came to power in Britain a few weeks ago. This is the way we want to come to power, as we did in Orissa. We want to come to power by the mandate of the people. We will not listen to the advice of people who say: "Let us topple Shrimati Indira Gandhi and then see what comes to India."

You cannot fight something with nothing. You have got to fight something with something better. I do not want to remove Shrimati Gandhi until I can put in her place a better Prime Minister and a better government. I do not want to bring chaos to the Centre as there was chaos in the State of North India under the SVD. We want, therefore, an alternative government to come into existence before we remove this government. That is why I believe this country needs above all an alternative government, a shadow Cabinet, which the people can judge and see sitting on these benches and say "Do we prefer that lot of people or do we prefer this lot?"

This is why when, on the 28th June, the AICC of the Opposition Congress passed a resolution putting a platform and a programme of action inviting other nationalist, democratic and socialist parties to respond, we responded, because we believed that that resolution met the needs of the time...(*Interruption*). The fact that some members of that party may have developed second thoughts and hesitations has nothing to do with it. Thoy Jid the right thing on the 28th June. So far as we are concerned, we shall be glad to respond to that kind of an appeal because that is the way in which we can create a force in this country which can challenge this Government, drive it to go to the people either in the coming months or not later than the time when an election is due, defeat this Government and then cross the floor. That is how the democratic change of Government must take place. For that we must work from now on till the time for an appeal to the people comes.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्री मधु लिमये की वाणी में जितनी शक्ति है और उन के गले में जितनी बुलन्दी है, सारा सदन उस से परिचित है। लेकिन आज

[श्री चन्द्र जीत यादव]

जिस प्रकार से हतप्रभ हो कर, निर्बल स्वर में और कमजोरी के साथ उन्होंने अपने अविश्वास-प्रस्ताव को पेश किया है, उसको देखते हुए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मतदान होने से पहले ही, उन के भाषण के साथ ही साथ उन का अविश्वास प्रस्ताव इस सदन में पराजित हो चुका है।

उन्होंने सरकार के विरुद्ध दो मुख्य बातें उठाई हैं। पहली बात उन्होंने यह कही है कि केरल में चुनाव की जो तिथियां निर्धारित की गई हैं और जिस प्रकार से मतदाताओं की सूची तैयार की गई है, उस से केरल में निष्पक्ष चुनाव की सम्भावना नहीं है। उन का आरोप यह है कि केरल में जो कुछ हो रहा है, वह केन्द्रीय सरकार के इशारे पर या केन्द्रीय सरकार के परामर्श या सहयोग से हो रहा है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लाने का कारण यह प्रस्तुत किया है।

मुझे ताज्जुब हुआ कि श्री मधु लिमये जैसे आदमी ने, जो समझबूझ कर और विचार के प्रश्नों को उठाते हैं केवल अपनी पार्टी की पुरानी नीति और परम्परा के अनुरूप इस प्रस्ताव को पेश किया है। उन के सामने आज प्रश्न यह नहीं है कि जिस विषय को वह उठाते हैं, उस में कितना तथ्य है, कितना बल है और वह कितना सत्य पर अधारित है। पिछले चार बरसों से उन की पार्टी की नीति यह रही है कि जिस प्रकार से भी हो, कांग्रेस का अन्ध विरोध करना है। जिस जगह भी, जिस सवाल पर भी उसे कांग्रेस का विरोध करने का अवसर मिलता है, वह उससे चूकती नहीं है। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार के विरोध का प्रश्न नहीं है। पिछले चार बरसों में कांग्रेस के अन्ध विरोध के कारण उस ने इस देश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों से, जिन का नेतृत्व श्री मसानी करते हैं, हाथ मिलाया है। इसी कारण वे लोग इस देश की सामप्रदायिक शक्तियों की गोद में बैठ जाते हैं, जिनका नेतृत्व श्री बलराज मधोक और श्री अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं। श्री मधु लिमये को आज उन तमाम शक्तियों और ताकतों की तलाश है, जो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर सकती हैं। इस में सिद्धांतों का सवाल नहीं है और न ही किसी बुनियाद का सवाल है। इस लिए मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि इस देश में सिद्धांतहीनता की राजनीति, कार्यक्रम के अभाव की राजनीति और जो कुछ भी हो रहा है, आंख बन्द करके उस का विरोध करने की राजनीति का युग समाप्त हो चुका है। जनता अब इस राजनीति को नहीं चलने देगी। इस लिए इस देश में उनकी और उन की नीति की पराजय अवश्यंभावी है।

मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस देश में चुनाव किस प्रकार होते हैं। क्या यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है? अपने संविधान का निर्माण करते समय हम ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह व्यवस्था की कि निष्पक्ष चुनाव की दृष्टि से चुनाव कराने, उन का सुपरविजन करने और मतदाताओं की सूची तैयार करने आदि कामों में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। हम ने यह महसूस किया कि अगर प्रजातंत्र की बुनियाद को कायम रखना है, उस को जीवित रखना है, तो निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, सही तरीके से चुनाव होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रख कर संविधान के अनुच्छेद 324 में यह व्यवस्था की गई कि चुनावों से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों का कोई सम्बन्ध नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रपति इस सम्बन्ध में एक चुनाव आयोग का निर्माण करेंगे, जो चुनाव के लिए मतदाता-सूची तैयार करायेगा, चुनाव के लिए तिथियां निर्धारित

करेगा और चुनाव की देख-रेख करेगा। अगर माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, की बात सही भी हो, अगर वह मतदाताओं की सूची से संतुष्ट न भी हों, तो भी क्या वह चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में हस्तक्षेप कर के चुनाव आयोग को आदेश दे कि चुनाव की तिथियां टाल दी जायें, या मतदाताओं की सूची को रद्द कर दिया जाये ? क्या वह चाहते हैं कि प्रधान मंत्री संविधान के अन्तर्गत बनाये गये चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप करें और उस को इस बारे में कोई आदेश दें ? मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार की परम्परा डाली जायेगी और चुनावों के मामले में इस तरह हस्तक्षेप शुरू हो जायेगा, तो जनतंत्र खत्म हो जायेगा। और यही माननीय सदस्य के अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ होता है। वह अनजाने में इस देश में एक ग़लत परम्परा डालना चाहते हैं। वह कांग्रेस के अन्ध विरोध के कारण प्रजातंत्र की बुनियाद पर आघात करना चाहते हैं और उसको समाप्त करना चाहते हैं। इस से देश का कल्याण नहीं होगा।

सी. पी. एम. के नेता, श्री राममूर्ति, ने बताया है कि केरल में मतदाताओं की सूची प्रिंटिड नहीं है और कार्बन कापियां साफ़ नहीं होती हैं। अगर ऐसी बात है, तो चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए कि सूची सही प्रकार से तैयार की जाये, प्रिंट की जाये और लोगों को आपत्ति करने का मौका दिया जाये। माननीय सदस्य इस बारे में चुनाव आयोग को परामर्श दें; अपील करें। अगर वह इस बात को नहीं मानता है, तो देश में जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हैं, वह उनमें अपील करें। लेकिन वह कृपा करके भारत के प्रधान मंत्री को चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप करने के लिए न कहें। अगर यह परम्परा डाली जायेगी, तो देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकेगा। इस लिए मैं समझता हूं कि यह सदन इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के माननीय सदस्य के पहले कारण को स्वीकार नहीं करेगा और उसके इस आरोप को ठुकरा देगा।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि केरल में जो सरकार है, वह केन्द्रीय सरकार की ऐजेन्ट है। वह तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने के आदी हैं। वह किसी को रूस का एजेन्ट कहते हैं, तो किसी को अमरीका का, किसी को बिड़ला का एजेन्ट कहते हैं और किसी को केन्द्रीय सरकार का। मैं कहना चाहता हूं कि केरल की सरकार केरल की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। वह केन्द्रीय सरकार की एजेन्ट नहीं है, वह भारतीय जनता द्वारा चुनी हुई एक प्रजातांत्रिक इकाई है। न हम उसके काम में हस्तक्षेप करना चाहते हैं न हम उसको बरख़ास्त करना चाहते हैं और न हम उसके लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहते है।

माननीय सदस्य ने कहा कि वहां मतदाताओं की संख्या 17 लाख कम कर दी गई है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 21 लाख बढ़ गई है। जब वहां की मतदाताओं की सूची तैयार की जाने लगी, तो उसमें कुछ लोग कम हुए और कुछ बढ़ गये। लेकिन यह बात सही है कि वहां पिछले चुनाव में 26 लाख लोगों को मत देने का अधिकार था, वहां आने वाले चुनाव में उनकी संख्या बढ़ कर 90 लाख होने जा रही है। अगर माननीय सदस्य को इस बारे में कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति करें। उनके सामने वहां दूसरे ऐवेन्यूज़ खुले हुए हैं। लेकिन वह कृपा करके इस प्रकार के निराधार और अनर्गल आक्षेप लगाने की कोशिश न करें। इस प्रकार प्रजातंत्र की या उसकी इकाइयों की मर्यादा नहीं बढ़ती है।

केरल में श्री अच्युत मेनन मुख्य मंत्री हैं। संविधान के अनुसार एक बहुमत दल के नेता

[श्री चन्द्र जीत यादव]

होने के नाते उन्होंने राष्ट्रपति को यह सिफरिश की कि वहां की एसेम्बली को भंग कर दिया जाये। हम उसमें किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकते थे ? जब संविधान में किसी भी मुख्य मंत्री को इस बात का अधिकार दे रखा है, तो भी क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार और उसके प्रधान मंत्री संविधान के विरुद्ध ऐसा आचरण करें कि किसी सरकार को बर्खास्त करें, किसी को मुख्य मंत्री बनायें और किसी को हटायें ? इस प्रकार की नीति में हम ने विश्वास नहीं किया है।

15.49 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

जब 1967 में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई कि कुछ राज्यों में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, तो प्रधान मंत्री ने भारत सरकार की ओर से नीति की घोषणा की कि हर एक राज्य में वहां की जनता को यह अधिकार है कि वह किसी भी दल को सरकार बनाने का सम्मान प्रदान करे। किसी भी सूबे के अन्दर किस पार्टी की सरकार बनती है, इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं होगा। जबतक सूबे की सरकारें अपने संविधान के अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनता के हितों में काम करेंगी, भारत सरकार उनको निरंतर अपना सहयोग देती जायेंगी और भारत सरकार अपनी इसी नीति का अनुसरण कर रही है चाहे वह मैसूर में चलने वाली इन्डीकेट की सरकार हो; चाहे केरल में सी. पी. आई. की सरकार हो या चाहे दिल्ली के अन्दर जनसंघ का एड-मिनिस्ट्रेशन हो, चाहे उड़ीसा के अन्दर स्वतंत्र पार्टी की सरकार हो। भारत सरकार ने इसी नीति के मुताबिक और संविधान के अन्दर जो प्राप्त अधिकार हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके साथ व्यवहार किया है। इसलिए इस लिए इस प्रकार के आरोप और आक्षेप जो किए गए हैं, मैं समझता हूं इससे संविधान या हमारे प्रजातंत्र को शक्ति नहीं मिलती।

दूसरी बात मधु लिमये जी ने कही और आरोप लगाया कि प्रधान मंत्री जी इस देश में तानाशाह बन रही हैं, प्रधान मन्त्री जी ने सारे अधिकारों का अपने हाथ में केन्द्रीयकरण कर लिया है और इस प्रकार इस देश के प्रजातंत्र को, देश की संसदीय व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है। मधु लिमये जी का मैं जानता हूं कि संसदीय व्यवस्था में विश्वास है, वे चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली इस देश में मजबूत हो। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या यह बात सही नहीं है कि प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी संसदीय व्यवस्था के अन्दर जो प्रधान मंत्री होता है या जो नेता होता है उसे इस बात का अधिकार है कि अपने विभागों का बटवारा किस प्रकार से करे, किसे मन्त्री नियुक्त करे, आज इस प्रकार का अधिकार अगर आपकी आलोचना से या एक एक व्यक्ति की सलाह से प्रयोग में लाया जाये तो कोई भी प्रजातांत्रिक रूप से सरकार काम नहीं कर सकती है। नहीं हो सकता है इस प्रकार का काम। मैं जानता हूं कि आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ। लेकिन अभी इस देश की जनता ने सौभाग्य आपको यह गौरव प्रदान नहीं किया है कि चव्हाण साहब को कौन सा विभाग देना चाहिए कौनसा नहीं, रघुनाथ रेड्डी को कम्पनी अफेयर्स का मिनिस्टर बनाना चाहिए या नहीं, ललित नारायण मिश्र को फारेन ट्रेड देना चाहिए या नहीं; इसके बारे में आप निर्णय करें। यह गौरव इस देश की जनता ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को दिया है, आपको नहीं दिया है और उन्होंने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया है। इस-लिए इस प्रकार की आलोचना जिसका कोई अधिकार नहीं है और जिसकी संसदीय व्यवस्था के अन्दर कोई परम्परा नहीं है, मैं यह निरर्थक आलोचना है। प्रधान मंत्री में इस बात को

महसूस किया, आज कोई नई बात नहीं है, जिस वक्त बंगलौर के अधिवेशन के बाद उन्होंने श्री मोरारजी देसाई से वित्त विभाग लिया उस वक्त आपने आरोप लगाया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी तानाशाह हो रही हैं, वे सारे अधिकारों को अपने हाथ में ले रही हैं। जब इस देश की जनता के अधिकारों की रक्षा करते हुए, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को समुन्नत बनाते हुए, इस देश की गरीब जनता की हालत को बेहतर बनाने के लिए प्रधान मंत्री ने महसूस किया कि वित्त मंत्रालय को वे अपने हाथ में ले और मोरारजी भाई से उन्होंने वित्त मंत्रालय लिया तो उस वक्त, आज के आप के सहयोगी सिंडीकेट के नेता ने भी यही बात कही थी जो आप आज बोल रहे हैं कि प्रधान मंत्री तानाशाह हो रही हैं. उन्होंने मुझे एक क्लर्क की तरह से डिसमिस कर दिया। इस प्रकार की बात उन्होंने भी उस समय कही थी जो आज आप कह रहे हैं।

मैं डा० राम सुभग सिंह को बधाई देना चाहता हूं और वह इस लिये कि जब तक डाक्टर साहब रेलवे के मंत्री थे, बहुत सारे एक्सीडेंटस जब रेलवे में हुए तो लोग उनकी बड़ी निन्दा करते थे, उनके ऊपर बड़े आरोप लगाते थे, कहते थे कि ये एक्सीडेंट मिनिस्टर हैं, तो यह बात आज साबित हुई। डाक्टर साहब की वह आदत सामने आई, डाक्टर साहब ने कल वह काम किया है कि इस देश के अन्दर जो प्रतिक्रियावादी शक्तियों का गठबंधन हो रहा था उसका यह सत्र शुरू होने से एक दिन पहले जिस प्रकार से आपने एक्सीडेंट कराया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं··· (व्यवधान)···इसीलिये मैंने बधाई दे दी।

यहां इस बात को कहा गया कि प्रधान मंत्री ने विभागों का बटवारा करते हुए कुछ हेरफेर मंत्रिमण्डल में किया है। जो सबसे बड़ा आरोप लगाया गया वह यह कि प्रधान मंत्री ने पर्सोनेल को होम मिनिस्ट्री से निकाल कर अपने अधिकार के अंदर, कैबिनेट सेक्रेटेरियट के अन्दर कर लिया। इस सदन में निरंतर इस बात की मांग थी कि हमारे देश के प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है। इस सदन की उस इच्छा को ध्यान में रखते हुए ए आर सी की स्थापना की गई। अब उसमें जो सबसे बड़ी सिफारिश है वह यह थी कि खुद एक पर्सोनेल का डिपार्टमेंट अलग से होना चाहिए। इतना बड़ा देश है, विभिन्न विभागों के अंदर लोगों की नियुक्तियां होती हैं, उसमें सामंजस्य नहीं रहता, कोई उस के अंदर एकरूपता नहीं रहती, इसको ध्यान में रखते हुये एक विभाग की स्थापना होनी चाहिए। प्रधान मंत्री ने उस सिफारिश को ध्यान में रखते हुये, उसको मानते हुये शासन को सुधारने की इच्छा से इस बार एक नये विभाग की स्थापना की; पर्सोनेल डिपार्टमेंट को। अब आपको इसके ऊपर भी एतराज हो रहा है। अगर एक सिफारिश की गई और अच्छी सिफारिश है; उसको लागू करके हम देखना चाहते हैं कि उस से हमारा प्रशासन बेहतर होता है या नहीं; उस के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की जाती है तो उसकी आप आलोचना करते हैं कि प्रधान मंत्री अपने हाथ में अधिकार ले रही हैं। आप इस बात की भी आलोचना करते हैं कि प्रधान मंत्री ने गृह मंत्रालय अपने हाथ में क्यों ले लिया कल वित्त मंत्रालय को ले लिया। आज प्रधान मंत्री किसी मंत्रालय को चाहें अपने हाथ में ले सकती हैं। पहले वित्त मंत्रालय को लिया था। आपकी आलोचना है कि प्रधान मंत्री ने बड़ा नालायकियत दिखलाई; जब तक वित्त मंत्री रहीं कुछ कर नहीं सकीं। अगर आपकी आलोचना को सही मान लें तो प्रधान मंत्री ने देश के हित में एक अपने लायक सहयोगी को वह विभाग अगर दे दिया है कि आप इसको चलाइये तो तब भी आपको दर्द होता है; तब भी आपको तकलीफ होती है। यह जो आपकी बटवारे की नीति है, डिवाइड एण्ड रूल की, मधु लिमये जी आप इस बात को याद रखिये, आप अपनी

[श्री चन्द्र जीत यादव]

नीतियों और कार्यक्रमों के ऊपर इस देश की जनता को संगठित करके इस देश में समाजवादी आंदोलन को मजबूत करना चाहें तो हम आप की सराहना करेंगे और आपके साथ सहयोग करेंगे लेकिन अवसरवादिता और सिद्धांतहीनता के आधार पर, सिद्धांतहीन विरोध के ऊपर आज आप जिन शक्तियों से हाथ मिलाना चाहते हैं; आज आपने डा० राम सुभग सिंह के साथ हाथ मिलाया और मुझे ताज्जुब हुआ कि डा० राम सुभग सिंह जी अभी थोड़े ही दिन हुये आप बलराज मधोक साहब से दूर ही बैठे हुए हैं लेकिन बलराज मधोक साहब ने जिस इंडियाना-इजेशन की थ्योरी को निकाला; आज आप उन की भाषा बोलने लगे ··(व्यवधान)···

डा० राम सुभग सिंह : गवर्नमेंट को बेच आये आप। यू० पी० की गवर्नमेंट यह नहीं है। यह सेंटर की गवर्नमेंट है (व्यवधान)···यह रशियन गवर्नमेंट नहीं है ··(व्यवधान)····

श्री चन्द्रजीत यादव : दूसरे मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि डा० राम सुभग सिंह आज यहां विरोधी दल के नेता हैं। एक बड़े सिद्धांत की बात उठाई गई कि प्रजातंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र की रक्षा होनी चाहिए, -शक्तियों का केन्द्रीयकरण हो रहा है प्रजातंत्र का हनन हो रहा है। मैं राम सुभग सिंह जी से पूछना चाहूंगा प्रजातंत्र में विरोधी दल के नेता का बड़ा महत्व-पूर्ण स्थान होता है, आज आप सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उस पद पर आसीन हैं, आप सरकार की नीतियों की आलोचना करिये लेकिन आज आपने जिस प्रकार से बात की, वह जो म्युनिसि-पल बोर्ड की राजनीति है कृपा करके भारत की संसद में उसको मत लाइये। कुनबापरस्ती और इस प्रकार के जो आरोप आपने लगाए; मैं यह कहता हूं प्रजातंत्र के लिए खतरा तभी उत्पन्न होगा जब लोगों के व्यक्तित्व के ऊपर हमला किया जाएगा, लोगों पर कुनबापरस्ती का झूठा आरोप लगाया जाएगा और इस प्रकार की बात की जाएगी; प्रजातंत्र के लिए यह सबसे बड़े खतरे की चीज है जिसकी आज आप रहनु-माई करते नजर आते हैं। आज शिव सेना की राजनीति को कृपा करके इस देश की संसद के अंदर मत लाइए कि कश्मीर का कौन राज करता है और कौन मैसूर का राज करता है। मैं कहना चाहता हूं चाहे वह कश्मीर हो, चाहे वह मैसूर हो; चाहे नेफा, सौराष्ट्र या नागालैंड हो, ये हमारे देश के अंग हैं। हमें इस बात का गौरव होता है अगर कश्मीर से आकर कोई हमारे देश का नेता बनता है या नागालैंड से आकर बनता है या नेफा से आकर बनता है। लेकिन इस प्रकार की बात अगर देश के अंदर पैदा की जाएगी तो वास्तविक रूप में प्रजातंत्र को खतरा और राष्ट्रीय एकता को खतरा पैदा होगा। आपने राष्ट्रीय एकता के ऊपर मजाक उड़ाया और आप कश्मीर का सवाल उठाते हैं कि एक आदमी कश्मीर से यहां आकर राज करता है। यह दुर्भाग्य है इस देश का।

16 Hrs.

श्री मसानी जी ने आखीर में तीन घण्टे के बाद अपनी राय बदल दी। तीन घण्टे पहले उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि हमें अविश्वास के प्रस्ताव पर खड़े नहीं होना है। तीन घंटे के बाद उन्होंने देखा कि यह जो सारा अनैतिक गठबंधन हो रहा है उसमें हमको भी सहयोग देना चाहिए और तीन घंटे के बाद वह बार बार मधु लिमये को इस बात का विश्वास दिला रहे थे कि हम आपके प्रस्ताव पर आपके साथ मत देने वाले हैं। मैं जानता हूं मसानी साहब एक बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं, वे इस प्रस्ताव पर नहीं बोलना चाहते थे; लेकिन उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और हमारे मित्र मधु लिमये साहब को समझाने का प्रयत्न किया कि स्टेट सोशलिज्म से

क्या खतरा है समाजवाद से क्या खतरा है और आपका समाजवाद का नारा इस देश के लिए कैसे खतरनाक है—इस विषय पर जब वह क्लास ले रहे थे तो उन्होंने समझाना शुरू किया कि स्टेट-कैपिटलिज्म क्या है, इसमें इंदिरा गांधी का दोष नहीं है; यह तो पूरे-के-पूरे प्लानिंग का दोष है, समाजवाद का दोष है और इस तरह से बतलाते हुए वह असली बात पर आ गये, उन्होंने कहा कि इस सरकार का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, अपनी कोई नीति ही नहीं है; व्यक्तित्व ही नहीं है, अपना कोई कार्यक्रम भी नहीं है। मसानी साहब और उनकी पार्टी की जो एक मुख्य कमजोरी रही है; वह यह कि उन्होंने कभी भी इस देश की तरफ नहीं देखा, इस देश की करोड़ों गरीब जनता की तरफ नहीं देखा; इस देश की स्थिति की तरफ नहीं देखा, उन्होंने हमेशा विदेशों की तरफ देखा, इस लिये उन को ख्वाब में भी वही दिखाई पड़ता है। इन्दिरा गांधी कोई भी काम करें, भारत सरकार कोई भी काम करे, अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार भारत सरकार कुछ भी करने का प्रयत्न करे—उन को नहीं दिखाई देता उन को उस में भी दोष ही नजर आता है। हम ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है—हमारी नीति—वैदेशिक नीति हो या आन्तरिक नीति हो—वह नीति है जो देश की जनता के हित में है, जो राष्ट्र की रक्षा करने वाली नीति है, जिस से हमारा सम्मान विदेशों में बढ़ता है, चाहे रूस हमें उस में सहयोग करे या न करे, चाहे अमरीका हमारे पक्ष में हाथ खड़ा करे या न करे, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, हम उसी नीति पर चलेंगे जो भारत की जनता के हित में होगी, देश के हित में होगी। इस लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश की जनता अब आप की इन निराधार बातों से गुमराह होने वाली नहीं है।

अन्त में सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भाषण यहां पर हुए हैं, ये सब उसी पृष्ठभूमि में हैं जो यहां पर पिछले 8-10 महीनों से घटित हुई हैं; जब से इस सरकार ने दृढ़-संकल्प हो कर मजबूती के साथ, पक्के इरादे के साथ, इस देश की गरीब जनता की जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिये, इस देश में व्याप्त सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए व्रत लिया है, इरादा किया है, चाहे जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मुसीबतों का सामना करना पड़े; चाहे थोड़ी देर के लिए लोग गुमराह भी हो जायें, सही बात को न समझ सकें, लेकिन यह सरकार दृढ़-संकल्प है, इस देश को समाजवाद की मन्जिल की तरफ लेकर आगे बढ़ेगी। इस देश के अंदर वे नीतियां ही लागू की जायंगी जो इस देश की जनता के हित में होगी। जब से इस सरकार ने यह संकल्प लिया है, तब से वे ताकतें जो इस को उस रास्ते पर जाने से रोकना चाहती हैं, परेशान नजर आती हैं और पिछले एक महीने से जो कुछ हुआ है—ग्राण्ड एलायेंस के नाम से, जिसके अन्दर सिण्डीकेट, स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ और दूसरी प्रतिक्रियावादी ताकतें शामिल हैं, जिन्होंने आपस में हाथ मिलाया है, उस में हमारे भाई मधु लिमये ने प्रयास किया कि किसी भी तरीके से ग्राण्ड एलायेंस न बने, लेकिन इन्दिरा गांधी विरोधी एलायेंस बन जाय तो उस में हम साथ देने के लिए तैयार हैं—लेकिन मुझे दुख है कि उन को इस काम में निराशा मिली, उन के सारे प्रोग्राम फेल हो गये उन को मायूसी का सामना करना पड़ा। इस से निराश होने के बाद आज उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव यहां पर पेश करने की कोशिश की है। सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पृष्ठभूमि में इस प्रस्ताव को यहां पर लाया गया है, उस का ध्यान रखते हुए; देश की जनता के हित में, देश की रक्षा के हित में जिन नीतियों पर चलने का दृढ़ संकल्प इस सरकार ने किया है उस संकल्प को दृष्टि में रखते हुए यह सदन इस अविश्वास प्रस्ताव को ठुकरा देगा, अस्वीकार कर देगा।

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : Mr. Chairman, we are a parliamentary democracy. We have adopted a Constitution and the Government is run according to that. Under that system, there are certain basic postulates, on the basis of which democracy functions. The first is freedom of speech, freedom of association and freedom of the press ; the second is free elections ; the third is majority rule and the fourth, collective responsibility of the Cabinet and its responsibility to the House of the People. During the last few months, all these four principles of democracy have been thrown to the winds. An example has been given how things are being done in Kerala, and how an attempt is being made to rig the elections there.

What has happened to freedom of speech I need not say. The entire country knows how the press is sought to be gagged, how the All India Radio and the other media of publicity have been gagged, how they are being used only for the party in power, how the people who stand for freedom and unity are being hauled up under section 153 (c) and how the people who preach secession are being lauded and eulogised.

Here I have before me two speeches. One is the speech of Sheikh Abdulla which he delivered at the convention in Srinagar in which he says that Kashmir will get independence, that the people of Kashmir will fight as the people of Algeria fought against France. And that man is the blue-eyed boy of Sadiq, and Sadiq is the right hand man of Prime Minister Indira Gandhi. And here is my speech, the report which the CID had taken. It is an absolutely wrong report. Even then, I will ask any hon. Member to read this. You will find that this Government is putting a premium on treason and trying to punish patriotism. This is the freedom of speech that we have.

Then, about majority rule. This is not a majority Government, this Government is in a minority, carrying on with the help of those who want to stifle democracy and the Constitution, who have made no secret of it. Here is a minority Government which has no right to be there.

Coming to the principle of joint responsibility, it is wrong to call this a Cabinet. In a Cabinet, the Ministers are colleagues, but here we find one Maharani and the others slaves. Therefore, in this case the principle of joint responsibility does not exist. The whole power has been concentrated into one hand, that of the Prime Minister, who has become Stalin and Hilter in one. Actually, Fascism and communism are only two sides of the same coin. Both concentrate power in one hand, both stand for totalitarianism. And this concentration of power is now, we find, in the hands of the Prime Minister, Mrs. Gandhi. She had the check to call Shri Vajpayee a Mini-Hitler. He may be a Hitler or he may not be a Hitler, but the Prime Minister, Mrs. Gandhi spent her early days in Germany. She saw how Hitler functioned, she herself admitted that she saw how he used to function, and she is trying to copy Hitler in this country. But I must tell her tha this country will not tolerate any Hitler or any Stalin. This is a democratic country, and it will remain a democratic country. But it is a challenge that has come to democracy from one person. This democracy is not only for the opposition. If democracy lives, then the parties exist, but if totalitarianism comes, whether Fascist or communist regime, there will be no Jana Sangh, no Swatantra Party, no Congress either. And therefore, it is for you to understand what you are doing. You are trying to sound the death knell of democracy in this country. She is taking the country towards that, and therefore, it is not only for me or for Mr. Madhu Limaye, but for all democrats to oppose it, and I know that there are many on that side also, I would like their conscience to wake up now, and it is for them to save the country.

Then, what kind of a Hitler or Stalin have you got ? Hitler at least had some commitment to his country, to Fascism ; Stalin had some commitment to his country, to communism ; but here is a Prime Minister who has commitment neither to democracy, nor to the country

nor to the party, who is committed only to herself. The way she stabbed her own party, the way she worked against her own candidate, is well known. I would ask any one of you to look into the political annals of any country. Can you find a single example of such political immorality which she indulged in ? First, she worked against her own candidate and then against President Giri. She wanted him to lose the Presidentship. It was the sixth sense, legal sense of the President that saved him. She wanted only a stooge President to rule, and since he was not behaving as such, she wanted him also to be out.

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : With all respect, may I rise on a point of order ? I do not want even a ruling from you, Mr. Chairman. I am only requesting my good friend Mr. Madhok not to drag the President into our discussions here..... (*Interruptions*).

SHRI BAL RAJ MADHOK : I do not drag in the President. The President is the head of the Republic of India ; he is the custodian of the Indian Constitution. When the Prime Minister is trying to wreck that Constitution and democracy, it is the responsibility of the President—I make an appeal to the President—to rise to the occasion and see that his Prime Minister does not stab democracy and wreck the Constitution. She is not only destroying democracy ; she is destroying the unity of this country. She has been encouraging communalism in this country and also the disruptive forces in this country. We condemn communal riots. When the British were there, her father the late Prime Minister used to say that it was the British policy to divide and rule ; there was Anglo-Muslim League alliance and they created riots. Now the British are gone ; for the last 23 years they are in power ; the Muslim League has got Pakistan. I ask them : Why are there riots now ? The simple answer is : they are following the British policy of divide and rule. The only difference is that the Anglo-Muslim League alliance has been replaced by Indira-Muslim League alliance. They are creating riots ; not only that ; they are encouraging disruptive forces all over the country. You know what is happening in Kashmir and in Assam. The Muslim League is raising its ugly head ; it stood for two-nation theory and it partitioned India and caused such a holocaust and so many murders ; crores of people were butchered and uprooted. That Muslim League is raising its ugly head under the patronage of the Prime Minister who claims to be working for national integration. She is the goddess, not of national integration, but of national disintegration ; she is working for disintegration. What she says is being used by those who are the enemies of this country. Here is a letter received by me from New York sent by "Honour India Committee:" 'I enclose here with a copy of the advertisement given by certain Muslim organisations. The contents of that advertisement are self-explanatory. They are anti-Indian'. The letter goes on further : "The sad story of the advertisement is that there are quotations from the speeches of the then Home Minister Mr. Chavan and the Prime Minister Mrs. Indira Gandhi in the advertisement." Here is the advertisement. The speeches of this hon. Lady who happens to be our Prime Minister are being used by our enemies, by Pakistan to malign India. She is behaving, not as Prime Minister but as an agent of Pakistan in this country. So we condemn her. Can there be greater shame for this country than that its Prime Minister's speeches and utterances should be used by the enemies of the country to malign our country ?

She has been talking of doing good to the people, to the common man. What is the result of the policies she has pursued during the last few months ? Prices have gone up by ten per cent. I am not a feudal lord like her ; unlike her I am a common man ; I do my own shopping. I know how prices are going up. She has never gone to the market and does not know what the prices are. The policies she is pursuing are anti-people. My friend Shri Chandra Jeet Yadav was speaking of people and perhaps he knows something

[Shri Bal Raj Madhok]

about people. But what does she know about people ? Let her go to the market and find out the conditions. What is the condition of salaried people, Government servants, five lakhs of them who live in Delhi ? Have they given them need-based wage or interim relief ? What is the condition of the nationalised banks ? There is a report in your own *National Herald* ; I have no time to quote ; these banks have become dens of corruption. You have not nationalised them ; you have bureaucratised them and all the evils of Government offices are coming in there and the common man is suffering. On the economic front she is ruining the country.

In respect of foreign policy, what have they done ? The other day Madame Binh was here as leader of an insurgent movement in Viet-Nam. There is a lawful Government there with which we have consular relations ; they have also a consul general here. In one country there can be only one lawful Government. Here comes an hon. lady who claims to be the leader of an insurgent movement and we treat her as a State guest. Persons who live in glass houses cannot afford to throw stones at others. We have a number of insurgent movements in this country. If tomorrow a friendly country invites Sheikh Abdulla or Charu Mazumdar and gives them the treatment you gave to Madame Binh, how will you feel ?

You have done all this because Russia wants it. You have made this country a satellite of Russia. Russia dictates our foreign policy, and our internal policy, and we look helplessly. But now Russia too is going away.

There is a distinct shift in Russian policy. Russia has been arming Pakistan. Russia put pressure on us in Tashkent and Shri Lal Bahadur Shastri died. You say that the Jan Sangh people killed Gandhiji. The Jan Sangh was not there; and after the trial that was held, the man who killed Gandhiji was hanged. But we ask, who killed Lal Bahadur Shastri ? There are doubts that he did not die a natural death. The whole house is demanding that there should be an enquiry into his death. And you are not coming out with an enquiry. Therefore I say, that they put pressure on us and took away the life of our beloved Prime Minister, the late Lal Bahadur Shastri. They are now putting pressure on us to succumb to Pakistani pressure about Farakka. And what have you done about Cambodia ? What have you done about East Asia ? Our entire foreign policy is in shambles. The result is that India honour is in dust.

Then, while you are talking of genocide this country, what has happened in Pakistan ? Two lakhs of people have recently come here from there ; they have left their hearths and homes after 23 years of freedom. They are rotting in Bengal as refugees. What is their crime ? Because they are Hindus. You went to Calcutta, but you had no time to go to meet those people. After all, if you had any human heart - you are a lady and you should have a human heart - that could have been done, but I think your heart also has gone; the milk of human kindness has disappeared from you because of power; the power madness. You never went to them. What is their crime ? Because they are Hindus. They are being driven out. There is continual genocide in Pakistan. When the country became free, there were 30 million Muslims in India and 15 million Hindus in Pakistan. In India we are proud that the Muslim population has gone up from 30 million to 60 million. But in Pakistan, the Hindu population has now come down from 15 million to eight millions. If there was any genocide, it was in Pakistan. But you are telling the whole world that there is genocide of Muslims in India. Nobody is going to believe you because facts disprove you. But you are maligning your own country. Have we not got the right to say about what is happening in Pakistan ? You say you have lodged your protests, and they do not listen. That shows your incompetence.

Therefore, during the last one year, this country has been brought to a pass which is really a matter of shame. More than shame, this country has come to a pass when its very future is in danger; democracy is in danger; the country's

economy is in danger; the country is in real peril. The whole power has got centred in your hands.

Here, I am reminded of George III. George III had centred all the power in his hands. And in those days, Burke said in the British Parliament, "The power of the Crown has increased, is increasing and must be checked." Today, I would appeal to this House the power of the Prime Minister has increased; is increasing and must be checked. And this can be checked not by the Opposition alone. When Burke made this appeal to the Members of the British Parliament, to whatever party they belonged, they felt it was the right thing to do; they worked together and they united, and finally they threw out that man who was trying to be a tyrant though he was the head of a democratic State. Similarly, today, my appeal to you all is all democrats and nationalists, to whatever party you may belong, whatever political philosophy you may have, whatever your economic policy may be - there might be differences of a minor nature-where the question of democracy is involved, where the question of national unity is involved, we should all become one. Today, in the true sense, freedom is in peril. We must all unite to save that freedom, to save that liberty.

Therefore, I would end my speach with the appeal to all democrats not only on this side, to all the nationalists not only on this side, but to all democrats and nationalists on that side also - they are in quite a large number there, and they may have some reasons for being there-but they are patriots; they are democrats, they are nationalists. I would appeal to you all. Your conscience awoke when there was a quarrel about two individuals - Reddy and Giri. Now, what is at stake are not two individuals. What is at stake is the country. What is at stake is the country's unity. What is at stake is democracy. Therefore, I would like to appeal to you : your conscience must awake ; Your conscience must arise. Now you must use your conscience and throw out this Government so that we can have a truly national, democratic government in this country, so that this country could be saved from the clutches of fascism and communism which are being tried to be imposed on this country by the Prime Minister who-one does not know whether she is a fascist or a communist. I think, is actually a facist and communist, both.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Sir, I am not surprised at the speech of Mr. Madhok, which it is bound to be, as it has always been, full of hatred and venom. That is the characterisation I would make of his specch. But I am really surprised at the specch of Mr. Madhu Limaye, who has always been claiming to be a democrat. I have no reason to doubt his honesty, but after hearing his speech, I am really sorry that he is falling from the pinnacle of glory of a democrat, which he has been claiming to be for a long time. Democracy is a form, but that is not enough. Its contents are more important. Election Machinery and adult franchise are its contents. Today he has derided the election Machinery which is enshrined in the Constitution itself. The laws of the country, including the Constitution must be respected, so that the freedom of the country and of the individual could be retained and preserved. Let us not, therefore, deride what the election Commissioner has done.

Let me ask Mr. Madhu Limaye what motive the Election Commissioner can have to manipulate the electoral rolls. Let me take up the points he has raised. If the Chief Minister advises the Governor to dissolve the legislature, should the Governor accept or reject that advice ? Can the Central Government go to the extent of advising the Governor either to accept or to reject the advice of the Chief Minister ? As a democrat who believes in the Constitution, what will be his answer ? Therefore, jet us not raise a question which is not germane to the topic. He wanted to condemn the Prime Minister for the concentration of power she has got because of the Cabinet reshuffle. That is the topic. But he has raised all sorts of questions, even going to the extent of condemning the Election Commissioner and at the same time asking

[Shri Bal Ra j Madhok]

the Central Government to intervene even at the time the advice was given by the Chief Minister to dissolve the Assembly.

Then he has raised the question of caretaker Government. He asked what right Mr. Achuta Menon's ministry had to continue in office. But is the caretaker Government a new, novel, foreign idea ? Is it not a constitutional phenomenon to be found wherever there is parliamentary democracy ? what is the use of blaming that Government which continues to be in office and which can continue under the Constitution at least for six months ?

SHRI NAMBIAR There is no Assembly there.

SHRI R. D. BHANDARE : I am aware that the legislature has been dissolved. But the caretakar Government can continue. That is exactly the convention I am talking of. That is exactly the idea which has been in existence for a long time in the country. Go to England or study the history of the English people, or the history of constitutional or parliamentary government; you will find that caretaker government is not a new thing.

Then he raised a pertinent question about the electoral rolls- how there could be an increase of 31 lakhs voters and a decrease of 21 lakhs of voters, This is not a new phenomenon. Perhaps, he has not studied how the electoral rolls are revised and how voters are included and excluded. Let me explain the point to allay his misgivings and silence criticism. Under the normal conditions the new Assembly should meet on the 26th of September. So, the Election Commissioner wanted to have an early election. There is nothing wrong if the elections are held earlier. It is only when the elections are delayed that we have a right to criticise it.

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : Rigged elections.

SHRI R. D. BHANDARE : If the elections are held earlier, how can you condemn it ?

Now, what is the factual position ? In 1964 the electoral tolls were revised intensively. In 1966 there was only Lok Sabha election; no Assembly election. So, there was no question of revising the electoral rolls intensively. In 1969 November there was intensive revision of electoral rolls. After publishing the cyclostyled or typed copies objections were invited, which is the usual procedure under the Representation of the People Act. In July 1970 an all-party meeting was held where the majority of the parties accepted the position of the electoral rolls. Only one party opposed it. The time was extended again up to 30th July, 1970, for inclusion and exclusion of voters and it was also carried. The increase of voters up to that time was 16 percent. As compared to 1964 there is an increase of 30 lakhs of voters and exclusion of 20 lakhs, leaving a net increase of 16 lakhs over a period of six years up to 15.1.70. Is it a phenomenon peculiar to Kerala ? No. The same phenomenon is found all over the country. In other areas also there has been an increase of 15 per cent of voters on an average. In Maharashtra the increase is 41 lakhs and exclusion 28 lakhs, leaving a net increase of 15 per cent of voters. So, there is no question of manipulation.

Then Shri Madhu Limaya raised the question of concentration of power and bureaucratisation in Government. Of course, the Prime Minister is competent enough to answer these charges, But may I ask Shri Madhu Limaye and people of his persuasion whether the Constitution has been subverted. Has the Prime Minister acted within the rights and privileges granted under the Constitution or has she subverted the Constitution ?

I was amused to hear Dr. Ram Subhag Singh. In this very House I had advised him to prepare himself to play the role of the opposition. But I do not think he has been able to either cultivate or understand the real role of the opposition. The role of the Opposition in this

House is based on hatred of the Prime Minister and the present Government. Looking at the speech made by Dr. Ram Subhag Singh, I have come to this conclusion.

What is the basis of their functioning in this House or outside? Have they given up socialism, secularism or democracy? What is the answer that the Congress (O) would like to give? They would like to enter into a grand alliance with Swatantra, Jana Sangh and C.P. (M).....(*Interruption*). Today at least you find them as their strange bed-fellow. It is really a strange combination. I am aware of the leaders of the Congress Opposition. They are under the impression that they cannot live without power because they have been in power for a long time. I am aware of the fact that they had played a very conspicuous part in the freedom struggle. But they are also responsible for the present state of the nation. The Congress Opposition has forgotten that for the present state of the nation they are also equally responsible.

As the time is passing, they are revealing themselves in their true colours. They cannot play the part of the Opposition. They are, therefore, confused and they have no policy, no programme at all. Therefore, they have no future at all. Let me ask one or two questions and I have done. Has Dr. Ram Subhag Singh given up the 10-point programme or has Mr. Masani accepted the 10-point programme? What is the position? Has Dr. Ram Subhag Singh accepted Indianisation as a philosophy enunciated by Shri Madhok or has Shri Madhok given up the philosophy of Indianisation? What is the position? The conclusion, therefore, is that the Opposition is based purely on hatred without any policy, without any programme at all. Therefore, they cannot have any future at all.

MR. CHAIRMAN: Shri Sezhiyan—not here; then, Shri Dange.

SHRI S.M. BANERJEE (Kanpur): Shri Dange will speak tomorrow.

MR. CHAIRMAN: I have no information. Shri Surendranath Dwivedy.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara): I will speak tomorrow.

MR CHAIRMAN: Dr. Karni Singh—he is also not here.

Shri J.B. Kripalani.

SHRI J.B. KRIPALANI (Guna): Mr. Chairman, Sir, I fortunately belong to no party. I, therefore, endorse the abuse that is given by the opposition to the ruling party and I endors the abuse that is given by the ruling party to the Opposition. I believe them both when they abuse each other. But there is something beyond that, beyond this party wrangle. That is what has recently been happening in our country. The previous speaker talked about forms of democracy and its contents. Will he tell me whether in any country a party works for the defeat of its own candidate? This is something that is not done in a democracy. Will he give me an example where a person proposes the name of a candidate and votes against that candidate? This is not done in a democracy. This is done when all laws, all procedures and all conventions are broken. When all these are broken, there is only confusion. In confusion also some people may prosper, but that is not democracy.

Again, take the recent instance of reshuffle of the Cabinet. Some ministers said that they could not manage a particular portfolio. They also said and their companions said that the new portfolios given to them were denigrating their position. I ask, is there any democracy in the world where ministers are chosen not because of their standing in the country but because the Prime Minister wants them? There is no democratic country in which ministers are chosen as they are chosen here now. Those who had some standing in the country have lost their standing.

I can understand that the Prime Minister sends for these people and tells them privately, "You please accept this portfolio that it will be for the good of the

[Shri J. B. Kripalani]

country or good for herself or her government. But if you carry on this controversy in public, what will the public think?

Is the public to believe the Prime Minister or Shri Dinesh Singh? We are put in a very awkward position. I believe both of them. That means, both of them are not giving the entire truth of what happened. What respect can the public have for ministers who have consented to be ministers, accepting the portfolios they did not want, for which they said that they were not competent, and that they were being denigrated?

Certain portfolios have been deprived of their power. That power is concentrated in the Prime Minister. This is something that is not done in a democracy. Where is joint responsibility then? How can I expect that Shri Dinesh Singh or Shri Chavan will exercise his judgment? Whenever a decision is taken, in this House we ask whether this was the decision of a minister or of the Prime Minister or of the Cabinet. Now there is going to be no decision of the Cabinet, except that of the Prime Minister.

They have accepted office against their best judgment. They have accepted office under coercion. The people believe-and they have a right to believe--that these Minister are enamoured only of their chair; otherwise, why should honourable people be have like that? After all, for them office should not matter. Why should a man, who is the leader of a whole province like Maharashtra, care for a ministership? But this is the position to which the Cabinet is reduced. Where is joint responsibility in this Cabinet? The Ministers are only the lackeys of the Prime Minister; that is all. Can minister be lackeys of the Prime Minister and not her colleagues. These things have been done. They are not done in any democracy that I know of.

Then there is another thing. Our members describe some party or the other as reactionary. Every democratic party believes in the Constitution. It swears by the Constitution. The members take their seats when they declare their allegiance to the Constitution. If they have declared allegiance to the Constitution and they have done nothing to violate it, then every democratic party, that believes in democracy, is not a reactionary party. Today in England who have been brought into power? The Conservatives. Can the Labour Prime Minister or a Labour Minister say that the Conservatives are reactionaries?

SHRI S. M. BANERJEE : Yes.

SHRI J. B. KRIPALANI : Every Opposition Party is considered as King's Opposition. This is necessary in a democracy. It performs important functions. As long as that party believes in democracy, it is not a reactionary party. If only the Labour Party or the Socialist Parties in other democratic countries are forward-lookihg parties, then there can be no change of government brought about by the people. People decide what will be good under the existing circumstances. They decide whether the Government should proceed slowly or if should proceed fast, whether you should adopt this reform or that reform and the people are free to choose whatever party they like, and no party can be called as a reactionary party.

Who are the reactionaries in a democracy? In a democracy those are reactionaries who do not believe in the Constitution, who subscribe to the Constitution only as a form. Who are the reactionaries? Reactionaries are those who believe in the totalitarian form of government, whether totalitarian rule is temporary or permanent, because every totalitarian government perpetuates itself. It cannot be removed. Dictatorship cannot be removed by the vote of the people. Those who believe in dictatorship, whether temporary or permanent, are the real enemies of democracy. They are the reactionaries and also those who have alliances with foreign countries are the reactionaries. They do not know even what democracy means. No democratic party in this country can be considered reactionary. The only reactionaries are those who be-

lieve in totalitarian rule and those who swear by the Constitution in order to break it so that they can produce confusion in the country. They think that in that confusion they can rise to power. Let me tell them that when confusion is created, nobody knows who will rise in power. In the beginning of the 19th century there was confusion created in France by the French Revolution. Did the French revolutionaries came to power ? Did those philosophers who preached that revolution come to power ? Did any of those come to power ? Who came to power ? Somebody from Corsica, a Subaltern. He became a dictator. He became an emperor. He became a conqueror. Then there was confusion in Germany. What happened ? It was not the German parties that came to power. Nobody, but a psychological idiot like Hitler came to power. There was confusion in India when the Moghul power failed. Who came to power ? Did our Maratha friends come to power ? They had come upto Delhi. They did not come to power. Not even the Sikhs who conquered the whole of Punjab. Neither Hyder Ali nor Tipu Sultan came to power. A foreign company of banias who came here to trade from 5000 miles came to power to our utter shame and remained in power for a couple of centuries. Nobody who is putting his faith in confusion will be able to bring our friend Prof. Mukerjee in power. I don't know whether he would like to be in power even after confusion. It will not bring in Ramamurthy into power. Remember, some people will come of whom we do not even dream, therefore, please be careful. Be careful not to create confusion in this country. Confusion can only be avoided if we observe the forms of democracy.

Now, what is hoppening in Bengal ? Is there any law and order there ? Things have happened in Bengal which did not happen even under Basu's rule. Every day bombs are being manufactured. Every day machine guns are being used. Every day universities are being closed. If this Government had used its power, if the writ of the Government ran, these things would not happen. Today, even the smallest Government has powers that if it wants it can crush any revolution. Revolutions, are not today made on the husting or on the barricades, where people had as good instruments to fight in the Nineteenth century as the Government had; but the people were more in numbers and therefore they counted. But today, the smallest Government has such weapons of repression that they can put down any rebellion.

And, what happened on the first occasion when the United Front Government fell ? There was a Governor there who acted and in 10 days' time nobody heard of the Naxalites. Then what did the Centre do ? They precipitated another election. That was the fault of the Central Government. Now, they have put in a Governor in power, about whom my friend Mr. Masani told the whole story. Do you know what his views are ? His views are the same as those of the Englishmen who were here. What did Englishmen come here for? They said that they had come to bear the burden of the 'White-man'; that they had come to civilise India. This Governor says, foreign rule is good because it is civilising Tibet Can foreign rule civilise any country ? No. It can only degrade the country. It cannot give it culture. It cannot make it mordern. We would have been more modern earlier, like Japan, if the foreign Government had not been here.

In Resolution after Resolution we said that the foreign Government had degraded us culturally, morally, economically and politically, in every way. So, foreign rule can never make people civilised. Foreign rule can only enslave people. If you appoint a Governor, who believes in the enslavement of the people, do you expect under line any law and order ?

I say, we are sitting on a vulcano. We must be careful and we must see that democracy survives—not one man's rule-but a joint rule, joint responsibility or the Cabinet or a Government, that is not a minority Government, that which does not depend upon those whom it condemns.

Jawaharlal used to say whatever may be the condition of the Communists in Russia, the Communists in India are reac-

[Shri J. B. Kripalani]

tionaries. These are his words. Why? Because, they want to destroy liberty, instead of adding to the welfare of the people. Instead of improving the condition of the poor, they destroy whatever liberty we have. Even starving people would not like to be deprived of their liberty. Any poor man in India will get better food better housing, if he only committed a robbery and went to jail for a couple of years and he will be very comfortable. But, does anybody do that? Does anybody do that? No, because liberty is something valuable. After all, what did our ancients say? What is the highest ideal? It is liberty; they called it *mukti*. *Mukti* is the highest ideal, not bread but *mukti*. *Mukti* must be combined, with bread but *mukti* must not be taken away because there is no bread. If there is no bread, give it to the poor. But do not take away their liberty. Do not take away what they already have. So, I say that it is very dangerous for this country to lose its democratic set-up.

As regards foreign policy, there was one madam who came here; whatever her name, I do not know...

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali) : Madam Binh. It sounds like dust-bin.

SHRI J. B. KRIPALANI : I hear that she was a very charming lady. I had no occasion to see her, and even if I had, my eyes-sight is not sharp enough.

Here we have Naga rebels and if they went to a foreign country which was a friendly country, with whom we had diplomatic relations and they had been welcomed them. I do know how we would feel. Since she was welcomed here, I do not know want has happened to this Government. I do not understand whether they have brains. Where have their brains gone? How could they entertain such a person?

SHRI PILOO MODY (Godhra) : They carry their brains in their petticoats.

SHRI J. B. KRIPALANI : Then they call themselves non-allgned. Does anybody believe that India is non-aligned? Everybody in the world believes that we are the stooges of Russia. There will be non-aligned conferences which will be held, where I do not know but somewhere it will be held. And Nasser will be a non-aligned person and Egypt will be a non-aligned country. This is utter nonsense.

SHRI S. M. BANERJEE : In Saigon, they had burnt our national flag and insulted our consulate. He never condemns that.

SHRI BAL RAJ MADHOK : We condemn the burning of the national flag not only in Saigon but also in Calcutta. But my hon. friend does not condemn the burning of the flag in Calcutta...

SHRI S. M. BANERJEE : We condemn everything.

MR CHAIRMAN : Order, Order. Let the hon Member be allowed to continue his speech.

SHRI S. K. TAPURIAH : Let them not hoist red flags.

श्री जी० भा० कृपालानी : आपस में पीछे लड़ते रहना, हम को तो बोलने दो।

When any one of them speaks, my hon. friends can make these interruptions. Let me be allowed to continue my speech.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : It is very good that our communist friends have at last developed respect for our national flag and a sense of houour for our national flag...

SHRI PILOO MODY : I suggest that all of us may get up and sing the national anthem.

SHRI S. M. BANERJEE : Nationalism is not the monopoly of Shri Samar Guha.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : Where was he when we were fighting the Britishers ?

SHRI PILOO MODY : Fighting the Britishers from Moscow ? Ask them if they have ever seen an Englishman ?

सभापति महोदय : जो लोग बोलते हैं बिना परमीशन के वह रेकार्ड पर नहीं जायगा ।

(Interruptions) * * *

SHRI J. B. KRIPALANI : They do not understand what has happened to our embassy. This is in retaliation to the reception that we gave to that lady. This is nothing more than that. No country would have done that. If our notional flag is burnt, I accuse this Government of having been responsible for that. Here is a country which is known to be friendly to Indians; this country is more friendly to Indians than Hanoi; Indians can live there and can enjoy all the privileges that no country has given to Indians. We entertained a rebel of that country and got our Embassy and national flag insulted. I hold this Government responsible for what has happened in Saigon, as I hold it responsible for having spoiled the internal politics of this country and the international politics of this country. Our boast that we are non-aligned is nonsense which nobody believes today except perhaps Russia. Behind the Iron Curtain, there are many non-aligned nations.

So if Egypt is non-aligned, well can India say it is non-aligned. This is how in politics words are used. Words seem to have absolutely no meaning, whetever they may say.

So, I say that I have no quarrel with our Prime Minister—I have no quarrel with her. What I have to quarrel with is this. She must not destroy the recognised norms of democratic behaviour. She must not do things that are not done in a democracy. She must not do destroy the respect in which we hold Ministers, the people hold Ministers and their subordinates hold the Ministers. If she degrades her Ministers, I say she is degrading herself.

I remember Gandhiji always praised us, always showered encomiums upon us, never degraded us in the eyes of others. To degrade your Cabinet is to reduce your Cabinet to a non-entity. That is all I have to say.

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : सभापति महोदय; पहले मैं मधु लिमये साहब को इस के लिए बधाई दूंगा कि इन्होंने ऐसे दलों का समर्थन ले लिया जो आपस में जिस ढंग से लड़ते हैं वह आप जानते हैं । उन्होंने कांग्रेस (प्रो) का समर्थन लिया; स्वतन्त्र पार्टी का समर्थन लिया जनसंघ का समर्थन लिया और श्री सी. पी. एम. का समर्थन लिया और आपस में जिस तरह से ये लड़ रहे थे यह आपने अभी देखा । यद्यपि डाक्टर साहब आज विरोधी दल के नेता हैं; वे इस समय उपस्थिति नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की भाषा का और शब्दों का व्यवहार उन्होंने किया है; बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने सदन के स्तर को बहुत निम्न स्तर पर लाकर रख दिया है । यद्यपि मैं जवाब देना तो नहीं चाहता हूं लेकिन यह कह देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह व्यक्तिगत आधार पर आरोप लगाये उसका मुझे दुख और कष्ट है । जिस दस्तख्त ने उन्हें कैबिनेट का मिनिस्टर बनाया, जिस दस्तख्त ने उन्हें इस गद्दी पर बिठाया उसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करना तो दूर रहा; जब उधर चले गये तो सारी कृतज्ञता धूलधूसरित हो गई । जब डाक्टर साहब 1952 में आये तो पहले पहल वे जगजीवन बाबू के साथ में थे; 57 में वे मोरार जी भाई के साथ में थे, 60 में पाटिल साहब के साथ में थे, 66 में चव्हाण साहब के साथ हुए और 1966 में फिर इन्दिरा जी के साथ हुए और सुन लीजिए तब से क्या किया उन्होंने ?

* * * Not recorded.

[श्री सीताराम केसरी]

जब मोरारजी भाई जोकि सिण्डीकेट राजनीति के गाजियन माने जाते हैं उनके नेतृत्व को भी उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और उनको भी धोखा दे करके वहां आ गए, इतना ही नहीं अभी जो ग्रैन्ड एलाएन्स होने वाला था इसलिए उन्होंने उसको तोड़ा कि वह नेता नहीं हो सकते थे क्योंकि मोरारजी भाई उसके नेता होते, इस बात की भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए उन्होंने इसको तोड़ा न कि सिद्धान्त में कोई मतभेद था। इस मामले में गहरे वे जनसंघ के साथ हैं, गहरे वह स्वतन्त्र पार्टी के साथ हैं। इस मामले में उनके विचार ज्यादातर इन दोनों दलों के साथ है। मगर चूंकि इस ग्राण्ड एलाऐंस के नेता मोरारजी भाई बन रहे थे, इस लिए उन्होंने इन दलों को एक होने से रोक दिया—इसका विरोध किया—यह इन के चरित्र का वृतान्त है।

मधोक साहब ने अभी हमारी प्रधान मन्त्री जी के सम्बन्ध में कहा कि वे हिटलर होना चाहती हैं। मेरा ख्याल है—गोलवल्कर साहब का भी एक चरित्र है, मैं समझता हूं वे झूठ नहीं बोलेंगे—उन्होंने आज से 23 साल पहले, उस समय भी वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक थे, पटना में भाषण देते हुए कहा था कि जब तक यह गांधी जिन्दा रहेगा, तब तक हिन्दू धर्म का कल्याण नहीं होगा....

17.00 hrs.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I challenge this statement. This is a wrong statement you are making here.

श्री सीताराम केसरी : मेरे दोस्त कहते हैं कि भारतीयकरण होना चाहिए। किस का भारतीयकरण होना चाहिए...(**व्यवधान**)... गरीब मुसलमानों का भारतीयकरण करना चाहते हैं। अरे उन का क्या भारतीयकरण करोगे, पहले उन का भारतीयकरण करो, जो खुले-आम अपनी जेब में माओ का फोटो ले कर घूमते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री बलराज मधोक : हम तो कहते हैं कि पहले इन्दिरा गांधी का हो, उन के बाद कम्युनिस्टों का हो, (**व्यवधान**)...

श्री सीताराम केसरी : मैं कहता हूं कि पहले उन का भारतीयकरण करो, जिन की लायल्टी इस देश के साथ नहीं है, जिनकी दूसरे देशों के साथ है, लेकिन आज आप उन के साथ वोट देने जा रहे हैं—यह है आप के अंदर की भावना, जो आज स्पष्ट हो गई है। जितनी बातें आपने यहां पर रखी हैं, ये सब व्यक्तिगत आधार पर रखी गई हैं, सिद्धांतों के आधार पर नहीं रखी हैं। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप ने आज जिन शब्दों का व्यवहार अपने भाषण में किया है, वे सब व्यक्तिगत आधार पर किये गये हैं। जब कि मधु लिमये साहब ने जो बातें यहां पर रखी हैं, उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर नही रखीं; राजनीतिक आधार पर उनकी चर्चा की है; यह दूसरी बात है कि हमें उन से मत भेद हो सकता है और बहुत सी बातों में हमें उन से मतभेद है। लेकिन वे इन लोगों की नब्ज को पहचानते हैं; कैसे इन लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए—वे इस कला को जानते हैं; इस लिए मैं उन को धन्यवाद देता हूं —उन्होंने इस लिए एकता की बात की; ग्राण्ड एलायेंस की बात की; क्योंकि उन को लड़ना था। ये लोग हिंसा की भावना से; बदला लेने की भावना से इतने ओतप्रोत हैं कि इन लोगों के सामने देश का हित नही है; राष्ट्र का हित नहीं है; इनकी अपनी दुर्भावनायें, जो इन के कलेजों में भरी हुई है; इन के विचारों से स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। इस लिए सारा देश आज इन से वाकिफ हो गया है; देश की जनता कभी भी इन की बातों से गाइड होने वाली नहीं है।

इन्होंने अपने भाषण में कहा—अखबार मालिक आज सरकार के साथ हैं—सभापति महोदय; यह तरीका है अखबारों को प्रेशराइज करने का। आज वास्तव में हो क्या रहा है, आप किसी भी अखबार को ले लीजिए; तमाम अखबार इन्हीं के फोटो छापे चले जा रहे हैं। इण्डियन एक्सप्रेस; टाइम्ज आफ इण्डिया; हिन्दुस्तान टाइम्ज--आप किसी भी अखबार को उठा लीजिये--भाषण दे रहे हैं तो फ्रंट पेज पर उन का फोटो छप रहा है फ्रंट पेज पर उनकी न्यूज छप रही है; जब कि यहां दूसरी बात कह रहे हैं। यह कहने का तरीका होता है; प्रेस को प्रेशराइज करने का तरीका है; धमकी देने का तरीका है; ताकि वे ज्यादा से ज्यादा इन के फोटो छापे .....आज जितने भी प्रेस वाले हैं; अखबारों के मालिक हैं; उन की हमदर्दी इन के साथ है; लेकिन कुछ सम्पादक या रिपोर्टर स्वतंत्र विचारों के भी हैं; उन पर दबाव डालने के लिए वे सदन में इस प्रकार के विचार प्रकट करते हैं- इस तरह से उनको प्रेशराइज करने का प्रयास किया जाता है और यही वजह है कि अखबारों में आप को फोटो या न्यूज हर जगह दिखाई देगी। मधोक साहब जेल जा रहे हैं; फोटो छप रही है; जैसे आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। कोर्ट में जा रहे हैं—फोटो छप रही है... (व्यवधान)...होटल में जा रहे हैं; फोटो छप रही है। अगर मधु लिमये फोटो छापना चाहेंगे तो तो कमी नहीं छपेगा, किन का छपेगा—मधोक जी का छपेगा। प्रकाश वीर जी भी इसी सदन के सदस्य हैं, उन के विचार इण्डीपेन्डेन्ट हैं; लेकिन आप कभी नहीं देखेंगे कि उन का कोई फोटो कभी अखबार में छपा है; जब भी देखेंगे मधोक जी का फोटो पायेंगे। यह क्या बात है ? ऐसा क्यों होता है ? हिटलर ने क्या किया था; उसने जर्मनी में सब से पहले माइनोरिटी कम्यूनिटी को विकटिम बनाया और बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को उन के खिलाफ उभारा और इतना उभारा कि लोगों के अन्दर यह भावना फैल गई कि जियूज हमारे देश के दुश्मन है; उन की लायल्टी जर्मनी के साथ नही है—इस तरह से उसका उदय हुआ। यही नीति मधोक जी की है—चाहे आप हों या अटल बिहारी वाजपेयी हों या गोलवल्कर जी हों—यह नीति देश के लिए घातक है और आप कभी भी इस में सफल नहीं हो सकेंगे और मैं आप के द्वारा; सभापति महोदय; इन से कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार का भारतीयकरण का प्रचार या अखबारों को प्रेशराइज करने की नीति अब नहीं चल सकेगी। राजपूत जाति नहीं; करैक्टर होता है, लो लड़ता है, लेकिन कृतघ्न नहीं होता है...(व्यवधान)... यहां मेरे दोस्त तापड़िया साहब बैठे हुए हैं जो राजस्थान से जीत कर आये हैं; लेकिन अगर वहां के बनिये यह जान जायेंगे कि इन्होंने सी० पी० एम० के साथ वोट दिया है; तो फिर इन को वोट नहीं मिलेगा...

श्री मनु भाई पटेल (डभोई) : सभापति महोदय; इस पवित्र सदन में जातियों का नाम क्षत्रिय, ब्राह्मण या बनियों का नाम लेना और इस तरह से जातियों का नाम लेकर बहकाने का जो प्रयत्न किया जा रहा है; क्या यह ठीक है; क्या यह इस सदन के सम्मान के अनुरूप है ?

सभापति महोदय : ऐसी बातें आप न कहें।

श्री सीताराम केसरी : सभापति महोदय, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। तापड़िया साहब और उन की पार्टी का कई बार स्टेटमेंट आया है कि वे सी० पी० एम० के खिलाफ हैं, सी० पी० एम० के साथ उन का कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन आज वह सी० पी० एम० के साथ हाथ मिलाकर चल रहे हैं....

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : हमने यही कहा है कि हम अन्याय के खिलाफ हैं

[श्री सु० कु० तापडिया]

अगर आप झूठी वोटर-लिस्ट बनायेंगे तो हम आप की खिलाफत जरूर करेंगे।

श्री सीताराम केसरी : बाहर तो यह कहते हैं कि हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन यहां उनके साथ दोस्ती कर के वोट देंगे—तो इस का क्या मतलब है। यहां सारे सिद्धांतों और सारी विचार-धाराओं को भूल जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर कहते हैं कि हम उन के खिलाफ हैं—यह विचार-धारा छुपी नहीं रह सकती। कलकत्ते में क्या हुआ—इन लोगों ने ही सी० पी० एम० वालों को पैसा दिया, बाहर कुछ रूप रखते हैं अन्दर दूसरा रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि जो अविश्वास प्रस्ताव मधु लिमये जी ने पेश किया है, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है और मैं समझता हूं कि सदन को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा तो यह है कि इसे वापस ले लें।

SHRI DATTATRAYA KUNTE (Kolaba) : Sir, a Government to be a Government of a nation, has to be judged on two points : one on the fiscal policy and the other on its foreign policy. As far as the fiscal policy of this Government is concerned, can this Government tell us that it has succeeded in its fiscal policy ? Merely the nationalisation banks is not going to help. If in the country of De Gaulle a number of years back, the banks were nationalised, can it mean that a socialistic step has been taken by a similar measure being adopted here ? The real point is that in this country, when so much unemployment is growing, and no attention is being paid to those unemployed, to talk of socialism, to talk of democracy, has no meaning. Therefore, in the matter of the fiscal policy of this Government, as far as unployment is concerned, this Government has dismally failed.

Coming to the other question, we are told that there is a green revolution in this country. No doubt it is true that in the areas where there is irrigation, there are better crops; science has helped. But it has helped the kulak class to grow. That has got to be remembered. If the kulak class grows, can there be real socialism ? That has got to be fought. That has got to be remembered. We are glad that punjab is having better crops. I am happy that Punjab is having better crops. But what are we going to do for the other parts of the country, the major part of the country which has not been able to have irrigation facilities ? Has the lot of the agriculturists been benefited there ? No. They have not been benefited, and as long the agriculturist is to depend on purchasing his foodgrains from others; and if they are only going to protect the price of foodgrains, we are only supporting the producers of the crops who own the lands and the fields, and not the poor workers of the nation.

This Government talks of socialism. Even today this Government has not been able to fix the wages of agricultural labour. The minimum wage for the city labourer, the industrial labourer has been fixed, but what are the reasons why this Government has not been able to fix the minimum wage for agricultural labour ? Will they be able to answer this question ? It is only because the Governments which support them in the States are having a large number of kulaks, those who have lands of irrigation and rich peasants. Therefore they are not prepared to guarantee the minimum wage to agricultural labour. And when big machinery is being imported, what happened ? People are talking of computers being imported. Instead of agricultural labour being utilised, machinery is being utilised. What is happening ? Agricultural labour is being thrown out of labour. Is there any remedy ? Has anyone thought it terms of those who are partially employed and are completely unemployed in the villages also ? Has anyone thought of it, and have there been any means to find out how they are being fed ? No answer is being given, and nothing is being done. If this Government is going to claim that it is doing the right thing, one must say it is not doing the right thing.

Coming to foreign policy, what do we find ? In the international field, even

after the devaluation that we suffered in the year 1962, even to today, India is a force to be reckoned with. Side by side it is the USSR, USA, China and India which are the major forces in this world. Out of these, the remaining three- USSR, USA and China- each of them is suspicious of the other and thinking which of the two will join faces with each other. Under these circumstances, if India follows a correct foreign policy, of independently judging the issues involed, India may have a different position and have a different status in the world. Today, this Government swears by the non-alignment policy of Pandit Jawahar Lal Nehru. By following that line, they might call themselves non-aligned. But Pandit Nehru was right in the old days; he said that he was not toeing the line of the USA. But now if we are to say that we are not toeing the line of the USA but are toeing the line of the USSR. that would be wrong. We find today, whatever the USA's position may be, it has walked out of Asia. Under the circumstances, this country has a responsibility of following a particular line in relation to her foreign policy. Therefore, on these two questions of fiscal policy and foreign policy, I must say this Government is not able to deliver the goods.

The two major questions of this country have been poverty and lack of sense of belonging. Can any one who talks against those who are talking of Indianisation say that we have created a sense of belonging in the people of India ? If we have not done that, Government has miserably failed. For instance, in the interest of toppling certain Governments here and there, a wrong policy is followed. What happened in Punjab ? At one time, Sant Akalis were bad. But very recently they have become very good. The person who talked before Mr. Kesari explained how it happened. He should not have thrown stones at others who try to protect somebody's Government. This very Government makes an alliance in Gujarat with the Swatantra Party to topple the Government there. How could you explain that ? I am only saying this to show that instead of basing things on religion or local issues and other things, really the attempt should be to create a sense of belonging.

Coming to the question of poverty, the poor man does not know where to go. With modern machinery and other things coming, the poor man is sent to the wall. During the last hundred years not only has the population grown but the pressure on agriculture has also grown. Previously 60 percent of the population were dependent on agriculture. Today 85 to 90 per cent of the population are dependent on it. with all the tall talk of land being given to the cultivactor what do we find ? In the Bengal Consultative Committee, the then Home Minister was pleased to say that he wanted to protect the cultivator and decide the share between the owner and the cultivator. In that land of Bengal where Right and Left Communists shave been ruling for a long time they have gone out of office because they quarrelled between themselves-today the landlord class remains. There are share-croppers and there are owners of land. How does this condition continue ? What has this Government done about it ? Only for the last three years, this Government has not been in power in the States. Before that, for 20 years, they were in power in the States. They only paid those who were able to hit against them, *i. e.* the industrial worker in the city. The poor agriculturist is being trampled upon both by the industrialists, the financiers and also by those who wield the power by handing over the power in the States to the kulaks.

These are certain points which should be noted when we are dicussing what sort of Government we have. Unfortunately one does not yet know what is the alternative. That is the only question for which I would seek a reply.

SHRI S. N. MISRA (Kannauj) : Sir. I have had occasion to analyse all that has been said by my friends opposite and I have been able to find that the underlying idea is not for the purpose of helping the country and the Government. The obvious reason is either discontentment with the party in power or discontentmens that they had to go to the other side. Dr.

[Shri S. N. Misra]

Ram Subhag Singh has spoken in very hard terms which I would say is unbecoming of a parliamentarian, particularly when he has been in power and he was a Minister. I would beg of him to keep his hand on his heart and say how he has acted earlier. There are other people also who have that feeling. But I suppose if they think coolly and analyse the working of the Congress Government the working of the ruling party, they would admit that the country has achieved during the short time something which neither America nor England have been able to achieve in less than a century. We have reached only the stage of the Fourth Plan. So, I would say to all those who are criticising us that it is impossible for any country to achieve what we have already achieved in this country in such a short time. Those who are not sitting on the ruling side, those who are sitting on the opposite side and criticising us, they have got only a distructive mind. It is very easy to criticise. It is only if they come forward and work they will know how hard it is to make conceptions realities.

श्री अब्दुल गनी डार (गुडगांव) : आप सच कह रहे है, किसानों के मकान सोने के बन रहे हैं, रिक्शा वालों के मकान सोने के बन रहे हैं।

شری عبدالغنی ڈار (گڑگاؤں): آپ سچ کہہ رہے ہیں کسانوں کے مکان سونے کے بن رہے ہیں۔ رکشا والوں کے مکان سونے کے بن رہے ہیں۔

श्री एस० एन० मिश्र : तकलीफ यह है कि आप के नहीं बन पाये। आप इसलिए चिल्लाते हैं।

श्री अब्दुल गनी डार : कहते हैं कि बड़ी तरक्की की है।

شری عبدالغنی ڈار: کہتے ہیں کہ بڑی ترقی کی ہے۔

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : सन् 1952 में आप भी हिन्दू महा सभा से चुनाव लड़े थे।

श्री एस० एन० मिश्र : हमने गलती रिअलाइज कर ली।

श्री जनेश्वर मिश्र : यह गलती भी आप रिअलाइज कर लीजियेगा दो वर्ष के बाद।

श्री एस० एन० मिश्र : पन्द्रह वर्ष के बाद देखा जाएगा।

Therefore, I would beg of My friends who sit in the opposition to keep their hands on their hearts and say whether this government has not succeeded in achieving what others could not achieve in such a short time. Therefore, I would oppose this motion of no-confidence.

MR. CHAIRMAN : Shri Sezhiyan.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : I will speak tomorrow.

SHRI BAKAR ALI MIRZA (Sicanderabad) : Mr. Chairman, Sir, nearly every session we have in one way or the other a vote of non-confidence and one wonders that we do not get tired of it. Probably it is because the hunger is not satisfied. The conditions in the country are such that require deep thought and attention by every citizen of India who loves his country. Bue what do we see today ? An atmosphere of defection is prevailing all over the country. No government is sure whether it well continue or not. Topping is a game that is going on all over the place, What were the reasons that brought about such a condition ? Have we progressed in this country ? Can we really help our country if we are following this policy ?

My complaint is with the Prime Minister. She has a very unique position. She has got the love of the country. She belongs to a family which is worshipped in India and whatever she does and says goes without question. Great hope was attached to her but her policies have not yielded the result.

Take, for example, secularism. When the Opposition Congress combines with the Jana Sang, it is reactionary and so on

[Shri Bakar Ali Mirza]

but when the Ruling Congress combines with the Muslim League or the Akali Dal, it is progressive. This is just because people have such regard for her that this thing goes and the contradiction is not obvious to the people.

Therefore if we have to move on, we must not think of personalities but only of principles. The main issue was that the Ruling Congress is a socialist body and it wants to have a social state in the country. But can you mention anything after the bank nationalisation which this Government has done which has led us forward toward socialism ? For the banks to be nationalised the Opposition Congress was in the way. They were removed and 14 banks were nationalised. Others asked for the nationalisation of foreign banks and, therefore, they were not progressive. We should have moved forward and done it. Did you do that ?

Take the question of land reforms. No State in which the Prime Minister has real power has taken a single step forward to introduce land reforms. Instead of that, they go round bluffing people. I come from Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh there is a Chief Secretary who owns more than 500 hectacres of land and nothing is said about that. What the Chief Minister does is that he distributed 2 million acres of Government waste land among 8 lakhs of peasants and say that that is land reform. Is that land reform ? If from the public sector you transfer it to the private sector, is it land reform ? In Maharashtra, in Bihar or in any State, tell me of the single step which this Government or party has taken after this re-organisation that has helped in land reforms.

Therefore talking socialism is one thing and really taking measures to bring this about is another. All of us are in the game of appearing progressive because being progressive has popular appeal. People are hungering for more land and growth. We come forward and say that we are going to do that ; therefore, follow us. So, the game today is to appear progressive; whether you are really progressive or not is a different matter. This is the condition today.

Then, the danger of Cabinet reshuffle is very great. After all, what is dictatorship ? Dictatorship is concentration of power in one political hand. The machinery that we have, Parliament and all that, is superfluous if power is concentrated in one hand. The Soviet Union also had elections and their Politburo. All the machinery were there but Stalin had all the power. All the power was concentrated in him and, therefore, he was called a dictator.

The way in which the reshuffling has taken place really saddens one's heart. People were made to believe that others are incompetent; they are not fit enough to work in a collective manner and that all the wisdom is concentrated in the Prime Minister. The Prime Minister of India has tremendous power. Other Prime Ministers have not used it. Our Prime Minister has used it to the full. The Home Ministry has all the accumulated power which has not been used so far. I wonder and shudder to think if that power is also used by our Prime Minister for this particular end.

Therefore, if democracy is to survive, if we are to grow as a nation and everyone is to have the confidence that we belong to a country which gives us an opportunity to lift ourselves without the support of others, then democracy must function realy in a definite and concrete form. Today democracy is really a bogus democracy and a shame. Therefore, I appeal through you to the House that some method should be evolved by which there is no concentration of power in one particular person howsoever just he might be. The very fact that there is concentration of power in one hand is a danger to the country. Even if angels from heaven descend when power is given because power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Surely, there is nobody who will not get corrupt when such enormous power is given.

The hon. Prime Minister talks of

having people behind her. I come from Telengana. For 3 years there was a movement for Telengana. After the movement was normalised, no attention was paid by the Prime Minister to the people of Telengana. The people of Telengana have got respect for her. Quite a number of persons are still in the Ruling Congress. In spite of that, she has paid no attention to them.

There is so much talk of Naxalites. They may kill people. But you also kill people. When in a State 300 people are killed in a cold-blooded manner, not a single judicial inquiry is set up. Only in one case, there was a magisterial inquiry conducted and even that was suppressed and the magistrate was transferred. What difference is there ? You allow the people to be killed by police action. And these people the Naxalites, kill people on some ideolo gical grounds. I do not see any difference between the two.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may try to conclude now.

SHRI BAKAR ALI MIRZA : I am concluding, I plead with the Prime Minister that at least the question of Telengana should be handled quickly as she promised before. Now, because she depends upon the support of the Chief Minister, everything the Chief Minister does is allowed. She should pay attention to the people of Telengana and take up the question of Telengana quickly. I have great regard for the Prime Minister. But I must tell her that what she is doing is not in the interest of the country might lead to greater disaster.

SHRI BEDABRATA BARUA (Kaliabo) : Mr. Chairman, Sir, as Mr. Masani said, this has become too much of a routine affair and, therefore, there need to be some sort of a change and that we need not start every session with a No-confidence Motion. I welcome such a suggestion particularly when we have a lot to do and we are, no doubt, facing situations and problems that are much bigger.

I am surprised that while so many political issues have been raised in the debate, the major economic issues, the problem of unemployment, etc. that have to be solved urgently have not been mentioned. We approach these questions in a spirit of dedication. This party has been taking steps in terms of revolutionising the economy of the country by bringing about radical transformation in the economy. Even those who swear by democracy today, who talk of democracy as if it would be lost if any socialist measure is undertaken, should realise that the people, the intellectuals, even in the United States have said that India's situation requires a radical and drastic remedy. Even those who are wedded to capitalism have co ne to this conclusion. An American expert once wrote that the combination of the Ford Foundation and the Communists would solve the Calcutta problem. This is what even these people say.

Here, the point is that this is a discussion which is not a discussion at all but an expression of a certain obsession on the part of the rightist opposition. Mr Madhok in his speech made a number of charges. In fact these charges have been continuously made for the last six months. He referred to England. He stumbled upon the trend in England—the growth of Cabinet power or the power of the Crown. If we make it as an intellectual discussion, there is possibly a lot to say. It may be possible for us to discuss those trends without bringing personal political predilections, not only predilections but personal political prejudices. We had a system which was by and large a capitalist economy where even the instruments of public opinion and the agencies of public opinion are also dominated by a group of monopolists. Therefore, by all available evidence there is concentration of political power and economic power. It is in fact a worse concentration of economic power in the hands of monopolists, a type of concentration which has been declared to be against the basic interests of our country because it has failed to develop the country. It requires a drastic remedy, a surgical remedy and during the last six

[Shri Bedabrata Barua]

months or more we have been thinking in terms of bringing about radical developments in our economy. In doing that we have certainly taken certain measures which have aroused the ire of the Swatantra Party or the Jana Sangh or of those people who suffer from more frustration, a party that was part of us. I do not know how Mr Madhu Limaye who shares socialist convictions, I think, with all of us can also see only one side of one aspect as a conservative would like to do. I would very much differ with Acharyaji when he says that reactionaries are those who have extra-territorial loyalties. He is not a reactionary, possibly he is something worse. But the basic question is : a reactionary wants to find out solutions of the problems in the past. But soulutions cannot be found in the past but only in the future. It is in this context that we have got certain problems. This is a problem which can be discussed. In fact on this side also there is a feeling that socialism cannot be brought about by an extension of the bureaucracy alone.

Mr Madhok quoted what was stated for the last 50 years in Britain that the power of the Crown has been increasing continuously. Laski formulated that the power of the Crown has increased. In India also the power of the executive Government has increased. Bureaucracy is growing and because it is functionless it is certainly a problem and this has to be discussed and some way has to be found out. This type of situation in which the functionless bureaucracy which is not capable of delivering the goods but wants more and more power—it has appetite for more power—but is incapable of implementing the decisions may create difficulties. It has not only to be discussed in terms of concentration of power. For example, in USA the power is concentrated in the President of the United States. I do not say that the power is concentrated in the Prime Minister here in the same way. But it is a fact that in spite of that all the power belongs to the President of USA, it is less according to me and more according to the Members of the Swatantra Party a democracy. At least I would call it as a capitalist democracy, a type of democracy I would not like to have in my country. In a democracy power is poly-centric. In that way political party and the Government cannot submerge the total freedom of the country. The Prime Minister in any democracy is called *primus inter pares*. He has not only to look to the homogenity of the Cabinet but it is also not accepted in the British Constitutional system that the Prime Minister functions under the principle of majority. So, the question does not arise and need not arise also, that the Prime Minister has to take away powers from anybody, particularly when the Prime Minister, under the Constitution, under British Parliamentary Practice, is authorised to look into the affairs of any Ministry or to interfere in any Ministry.

Therefore, this obsession about certain powers being transferred to Prime Minister's Secretariat is a thing which it most misleading and it does not do any honour to the Opposition in this House to emphasise it too much. Because, it is a matter in which our party is involved and our party is interested. No doubt there had been certain trends in our country and we had been trying to counter those trends. By countering those trends, we are trying to make an effective functioning of parliamentary democracy possible in this country. It is not that we have not made any mistakes at all. If we have erred at all, if we have committed any mistake, it is in the direction of being too democratic, allowing the bureaucracy and the political system to operate under a scheme of checks and balances that have allowed us, or rather, forced us to function rather incompetently.

Now, this is a situation that can be solved and solved only by looking at the political and economic and administrative systems as a whole from a different angle, and in terms of major reforms in the administrative, political and economic systems.

I have no doubt that what the Prime Minister has done is a step in the right direction. And, therefore, danger to democracy cannot come from that angle. When danger to democracy comes, it does not come by the concentration of power in a political party, even supposing that power is concentrated. Because, after all,

democracy depends upon various institutions of democracy and agencies and free institutions etc. Just to carry conviction, I would like to quote what foreign press had said. One of the foreign visitors who had come to India said that Indian Press is more free and somebody said, it is embarrassingly free. He said it is so free that possibly few countries would have equal freedom of the Press as we have in India. That is the type of opinions that have been expressed. One may contradict it but it is a fact and you may look at any cartoon, or any report or any editorial in town newspapers that have got large circulation. You may pick up anyone and see. You will find always the same story, the same slant, a particular political opposition to change and a particular prejudice working throughout and we are functioning under this system of propaganda —political and otherwise— which has endangered our democratic structure as well.

Therefore, Sir, if we are really to make a success of our democracy we have always got to realise that the type of slant that is given out by the Swatantra Party and the Jan Sangh party in regard to law and order situation is the most dagerous and fascist of tendencies that we find in this country. Because, Hitler's Fascism arose out of his very intolerance of the expression of discontent. Expression of people's disconent has to be solved by socio-economic approach, by solving their economic problems, by looking at their problems from a particularly progressive angle. It is only thus that these problems can be faced. Hitler wanted to solve those problems by introducing an economy which is totally intolerant. He wanted to suppress expression of opinion as our Swatantra friends wanted that the Communist Party must be banned and that the only solution is the solution of the bullet. It is this trend that I consider the most dangerous to our democracy.

In fact, if our democracy faces danger today, it is the danger of polarisation of ideas in directions of extremism.

In fact, no democratic structure can function if the Naxalites become sufficiently strong or as strong or have at least the type of strength that Jan Sangh has. Certainly, the functioning of democratic system requires certain basic agreements among the opposition and the ruling party and this may break down slowly, and this is a real danger to democracy.

The tendency of the political systems to work at cross-purposes, the parties not being agreable to agree on fundamentals, is the worst danger to our democracy. All these dangers to democracy came particularly in a sinister manner when banks were nationalised and when socialist measures where adopted and when it was expected by many and feared by some that they would bring about a radical transformation in the economy. All the resistance which was given by the rightist parties has been exaggerated by the type of resistance from my socialist friends like Shri Madhu Limaye ; for all practical purposes, they also joind with those forces in trying to submerge socialism; in practical effect at least it does submerge or it seeks to submerge the socialist directions that we are trying to give to our economy.

It is in regard to foreign policy again that a major attack has been launched. It is an attack which has been launched not only in this House but in the country, that our foreign policy has become a policy of satellitism, and that we have become a puppet of the Soviet Union and that the Soviet Union is dictating our policies and that whatever stand we take is due to the directions coming from the Soviet Union. I do not think that there can be a greater exaggeration than this. If democracy is to function, I would beg of my hon. friends to see that there can be many shades between black and white. Therefore, it will not do to say that India has become an autocratic regime. It is simply not a fact. Parliament would not have been there if India had been autocratic, and the freedom that we have now would not have been there. But the point is that to say that we are a satellite of the Soviet Union is a complete misstatement of facts. We do have our policies,

[Shri Bedebrata Barua]

During the last twenty years, we have placed our policies in a particular light. We wanted to be non-aligned and we wanted to be anti-imperialist. In Viet Nam, when we opposed the Americans, and when we invited Madam Binh, it has been very strongly criticised in our country. It is said that she was just a Naxalite in Viet Nam. But is she actually a Naxalite in Viet Nam ? That is our question. In fact, Madam Binh also represented her country, and the symbol of Western democracy, namely the United States did have talk with Madam Binh in Paris on these matters. Our nationalist movement once was also an opposition movement or anti-imperialist movement. But that is another matter. For Madam Binh rules a government which has got a communist ideology. But it is also a fact that in Viet Nam as the situation is today, the nationalist, movement has been led by the communists, tnot only today but from the beginning; here was no other leadership in the nationalist movement in Viet Nam. What are we going to do in in that situation ? For us, it appeared very clear that so far as Viet Nam was concerned, the American intervention has been like a bad surgeon's surgical operation, ever extending the wound. It has extended the wound to Cambodia. It may extend the wound to...

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What about Czechoslovakia ?

SHRI BEDABRATA BARUA : I would refer rather to Yugoslavia. Why not experiment with this idea that after all the Vietnamese who have resisted the Chinese for three thousand years of their history would still resist the Chinese? Why not make Viet Nam a Yugoslavia in Asia ? Why not examine the possibility of a people who have been fighting against American imperialism for decades ? Why not accept their capacity to resist any other form or mode of intervention in their affairs ? Why is it necessary for us to imagine that....

SHRI RANGA (Srikakulam) : Do not be so blind. What happens when your Naga leader goes to China and to Pakistan and he is recognised somewhere as she has been recognised here ? Why is he so blind ?

SHRI BEDABRATA BARUA : I am not being blind. I think it was this blindness which led the Americans to hand over China to Mao Tse-tung. It is this blindness again that is now endangering the independence of Cambodia.

SHRI P. G. SEN (Purnea) : Why have you kept our Embassy there ? Why not close it down ?

SHRI BEDABRATA BARUA: We have always recognised the regime that exists. Our position is that that government has been recognised because it is a *de facto* government...

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Why did you invite her officially ?

SHRI BEDABRATA BARUA : At the same time, the Government of Madam Binh is a revolutionary government.

SHRI RANGA : The Nagas also have got a revolutionary government.

SHRI BEDABRATA BARUA : Her Government is different from the government of Phizo or any other emigre government. It does have control over large territory.

SHRI RANGA : He comes from so near that area where the Naga hostiles operate. Why is he so blind to facts ? There must be a limit to blindness.

AN HON. MEMBER : If the UK Government invites Phizo's Government, will he like it ?

SHRI BEDABRATA BARUA : I would say to Shri Ranga that the whole danger to our democracy and to our freedom comes from people who are not able to understand the powerful and inherent forces working in the world today ; it is not by blindness that one can confront those forces.

SHRI P. G. SEN : For the sake of one lady, you have endangered the lives of so many Indians.

AN HON. MEMBER : You do not recognise East Germany. That is not a revolutionary Government ?

SHRI KANWARLAL GUPTA : I hope the Prime Minister agrees with his views.

SHRI BEDABRATA BARUA : I am expressing the view of the party as I understand it.

SHRI KANWARLAL GUPTA : Is that the official view of the party ?

SHRI BEDABRATA BARUA : It cannot be the official view of the Government, but it needs also to be expressed by a member of the party, as he understands it.

I would strongly reject this idea that we are a satellite of the Soviet Union or for that matter of any foreign power. We have resisted all types of incursion. Our party is born out of a big nationalist movement.

AN HON. MEMBER : What happened to Dubcek ?

SHRI BEDABRATA BARUA : Ours is a vast country. India is not going to face the fate of Dubcek. On international issues, we have been friendly with the Soviet Union. We cherish that relationship we have with the Soviet Union. The Soviet Union has given us assistance and friendship which we greatly need. At the same time, we are, as one Soviet leader put it, a country of 500 million. He said, 'Do not forget that you are a country of 500 million. We may have friends. To have friends does not mean that we are under them any more than saying that to have an enemy means that we at war with him. We do think of our own interests, national and international; we do have in view our own development, our own growth, our own future. We do have a foreign policy suited to our interests; in view of the very troubled situation of the world today, with Pakistan and China posing as our enemies, we do need to have friends in the world and we do not feel ashamed of having friends in the world. We would like to develop the same type of friendship. It is not a question of a rigid approach that will help us.

Reference was also made to communal riots. We know how these riots had taken place, what was their origin and how much necessary it is for us to teach the people, both Hindus and Muslims, and make them understand the basic reason for these riots and how some people who have been constantly instigating these riots need to be also taught to behave properly.

Then again it is a misstatement of fact to say that our part is not for land reforms. In fact, ours is the one party which decided—I am speaking on behalf of the party—that even if the party in power in a State is the Congress Party, we would carry on the movement for land reforms in that State, and in other States also. As I said, it is a misstatement of fact to say that we have not carried through land reforms. Even today we have supported land reforms in Bihar; we are bringing in legislation there.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, सदन जानना चाहता है कि कब से भूमिसुधार कानून में इनकी दिलचस्पी है, यह बता दें अगर इनको जानकारी हो, अगर न हो तो हम नहीं चाहते। भूमि-सुधार की बात कब से चल रही है ?

SHRI BEDABRATA BARUA : I have no reason to reply to a particular question.

I only say this much in conclusion that so far as land reforms are concerned though we, members of legislatures, raise slogans against the capitalists and landlords, when it comes to land reforms, our attitude is short through with the interests of the landlords. This is so in all political parties, not only in my party but in the case of all political parties. We resist

[Shri Bedabrata Barua]

land reforms; it is obvious, it is known to everybody. This is what has to be fought.

SHRI M. MUHAMMAD ISMAIL (Manjeri) : It is strange that the question of elections in Kerala has been made one of the reasons for supporting this no confidence motion by some of our friends, and it is stranger still that the people who want elections in West Bengal,...

SHRI UMANATH : Free and fair elections.

SHRI M. MUHAMMAD ISMAIL : ... I am coming to that, do not want such elections in Kerala.

SHRI UMANATH : Rigged elections, that is the point.

SHRI M. MUHAMMAD ISMAIL : They brought out some reasons for not wanting this election just now in Kerala.

The election is being conducted not by the Central Government. Under any democracy there must be some agency independent of the Government to conduct elections, and there is such an agency in India also, and that is the Elections Commission. They are carrying on their work, preparing for the elections, preparing the electoral rolls according to rules, according to their programme, according to their schedule, and such work has been carried on throughout the country including Kerala.

The last such operation took place between 15th November and 30th November, 1969, when the electoral rolls were revised throughout the country, and in Kerala the same operations took place. All the parties were informed of those processes by the Election Commission. At that time no such question as is being raised now was brought up.

Just before that time, the Namboodiripad Government was in existence in Kerala. Then also this work of revision of the electoral rolls was taking place. After that, on the basis of the electoral rolls prepared as a result of the operations of the Election Commission between 15th and 30th November, 1969, three bye-elections have taken place in Kerala. At that time too this question of something being wrong with the electoral rolls was not brought up before the authorities.

MR. CHAIRMAN : He may continue tomorrow.

BUSINESS ADVISORY COMMITTE FIFTY-FIRST REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING & TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : I present the Fifty-first Report of the Business Advisory Committee.

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 29, 1970/Sravana 7, 1892 (Saka).